www.deshkiupasana.com

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक समाचार पत्र

RNI NO - UPHIN/2022/86937

जौनपुर से प्रकाशित

देश की उपासना

देश के विकास में समर्पित समाज के सभी वर्गों के लिए

DKU LIVE

सब पर नज़र, सबकी ख़बर

वर्ष – 04 | अंक – 153 | जौनपुर शनिवार, 17 जनवरी 2026 | सान्ध्य दैनिक (संस्करण) | पेज – 4 | मूल्य – 2 रूपये

संक्षिप्त खबरें

दिल्ली कोर्ट ने आप के पूर्व विधायक नितिन त्यागी के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया

नई दिल्ली, (एजेंसी)। दिल्ली की एक अदालत ने 2019 में एक निजी निर्माण कंपनी के कर्मचारियों को परेशान करने के मामले में आम आदमी पार्टी के पूर्व विधायक नितिन त्यागी के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया है। त्यागी और उनके साथियों पर आरोप है कि उन्होंने 29 नवंबर, 2019 को यमुना के डूब क्षेत्र की बहाली और पुनरुद्धार के लिए काम पर लगाए गए कर्मचारियों के साथ मारपीट की थी। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नेहा मित्तल ने 13 जनवरी के आदेश में पूर्व विधायक के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धाराओं 427 (50 रुपये या उससे अधिक का नुकसान करने वाला शरारती कृत्य), 323 (जानबूझकर चोट पहुंचाना), 186 (सार्वजनिक कार्य में बाधा डालना) और 34 (सामान्य इरादा) के तहत आरोप तय करने का आदेश दिया। हालांकि, अदालत ने उन्हें किसी भी सरकारी अधिकारी को चोट पहुंचाने, हमला करने या आपराधिक बल प्रयोग करने से संबंधित अपराधों से मुक्त कर दिया।

'पार्टी-विरोधी गतिविधियों' के लिए बीजद ने दो विधायकों को निलंबित किया

नई दिल्ली, (एजेंसी)। विपक्षी बीजू जनता दल (बीजद) ने अपने दो विधायकों – अरविंद मोहपात्रा और सनातन महाकुड को "पार्टी विरोधी गतिविधियों" के आरोप में बृहस्पतिवार को निलंबित कर दिया तथा संकेत दिया कि वे "भ्रष्ट और देशद्रोही" हैं। पार्टी ने हालांकि केंद्रपाड़ा जिले की पटकुरा से विधायक मोहपात्रा और क्योंझर जिले के चंपुआ निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले महाकुड द्वारा कथित रूप से की गई पार्टी विरोधी गतिविधियों की प्रकृति को स्पष्ट नहीं किया। नवीन पटनायक द्वारा हस्ताक्षरित आदेश के मुताबिक, पार्टी–विरोधी गतिविधियों में संलिप्तता के कारण उन्हें (दोनों विधायकों को) बीजू जनता दल से तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। मोहंती ने कहा, ''उचित प्रक्रिया का पालन करने के बाद, दोनों को पार्टी से तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।'' उन्होंने आगे कहा कि राज्य भर के पार्टी कार्यकर्ताओं ने इस फैसले का स्वागत किया है। पहली बार विधायक बनने वाले मोहपात्रा 2024 के विधानसभा चुनावों से लगभग 18 महीने पहले बीजद में शामिल हुए थे और उन्होंने निलंबन पर आश्चर्य व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि उन्हें इस फैसले की जानकारी सोशल मीडिया के माध्यम से मिली और उन्हें अपने खिलाफ लगे आरोपों का पता नहीं है। मोहपात्रा ने कहा, ''अगर आवश्यकता पड़ी तो मैं बीजद अध्यक्ष से मिलना चाहूंगा।'' महाकुड ने कहा कि उन्हें इस कदम से आश्चर्य नहीं हुआ और 2014 में एक निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुने जाने के बाद, वे बीजद में शामिल हो गए।

बीते एक दशक में स्टार्टअप इंडिया मिशन क्रांति बना, लाखों लोगों के सपने हुए पूरे : पीएम मोदी

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को कहा कि बीते 10 वर्षों में स्टार्टअप इंडिया मिशन क्रांति बन चुका है। भारत आज दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। इस योजना ने लाखों लोगों के सपने पूरे करने में मदद की है। राष्ट्रीय राजधानी में स्थित भारत मंडपम में स्टार्ट इंडिया मिशन के 10 वर्ष पूरे होने पर लोगों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, आज हम स्टार्टअप इंडिया के 10 साल पूरे होने का माइलस्टोन सेलिब्रेट कर रहे हैं। 10 साल की यह यात्रा सिर्फ एक सरकारी योजना के सफल होने की कहानी नहीं है, यह आप जैसे लाखों सपनों की यात्रा है।इस मौके प्रधानमंत्री ने स्टार्टअप इंडिया मिशन में योगदान देने वाले युवाओं की सराहने करते हुए कहा, हमारे यंग इनोवेटर्स, जिन्होंने नए सपने देखने का साहस दिखाया, मैं उन सभी की बहुत–बहुत सराहना करता हूं। कार्यक्रम में आगे बोलते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, ष्आप याद कीजिए, 10 साल पहले हालत क्या थे। व्यक्तिगत प्रयास और इनोवेशन के लिए गुंजाइश ही नहीं थी। हमने उन परिस्थितियों को चौलेंज किया, हमने स्टार्टअप इंडिया लॉन्च किया और हमने युवाओं को खुला आसमान दिया और आज नतीजा हमारे सामने है। सिर्फ 10 साल में स्टार्टअप इंडिया मिशन क्रांति बन चुका है। भारत आज दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है।ष प्रधानमंत्री ने आगे कहा, ष्10 साल पहले, देश में 500 से भी कम स्टार्टअप थे, आज यह संख्या बढ़कर दो लाख से ज्यादा हो गई है। 2014 में भारत में सिर्फ 4 यूनिकॉर्न थे, आज भारत में करीब 125 सक्रिय यूनिकॉर्न हैं। दुनिया भी आज इस सक्सेस स्टोरी को हैरानी से देख रही है। आने वाले समय में जब भारत की सक्सेस स्टोरी की बात होगी, तब यहां बैठे कितने ही युवा खुद में एक ब्राइट केस स्टडी बनने वाले हैं।

अमित शाह करेंगे बांसेरा पतंग महोत्सव का शुभारंभ

नई दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शुक्रवार को दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) के तीसरे अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। पंतग महोत्सव का आयोजन राष्ट्रीय राजधानी में सराय काले खान के पास यमुना के बाढ़क्षेत्र में स्थित बांसेरा घास के मैदानों पर किया जाएगा।डीडीए के उपाध्यक्ष एन. सरवाना कुमार ने तीन दिवसीय कार्यक्रम के निमंत्रण में बताया कि उद्घाटन समारोह शुक्रवार दोपहर करीब 12 बजे बानसेरा के बिरसा मुंडा चौक पर होगा। अगस्त 2024 में, डीडीए ने दिल्ली के सराय काले खान के पास बांसेरा में यमुना के बाढ़ के मैदानों पर पुनर्स्थापित घास के मैदानों का दौरा करने के लिए नागरिकों को आमंत्रित किया।डीडीए अधिकारियों के प्रयासों की सराहना करते हुए उपराज्यपाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में क्षेत्र के परिवर्तन को दर्शाने वाला एक छोटा वीडियो भी संलग्न किया और कैप्शन दिया, ष्बांसेरा–बदहाली से हरे–भरे नखलिस्तान के रूप में पुनर्स्थापन। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2030 तक देश की 2.6 करोड़ हेक्टेयर बंजर भूमि को पुनर्स्थापित करने के विशाल दृष्टिकोण से प्रेरित होकर, मैंने उपराज्यपाल का पदभार संभालने के तुरंत बाद, 28 मई, 2022 को दिल्ली में एक छोटा सा कदम उठाया।उपराज्यपाल सक्सेना ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि रिंग रोड पर सराय काले खान के सामने यमुना के बेहद प्रदूषित और दूषित इलाके का दौरा करते समय, बांसरा, बांसों का घर की कल्पना की गई। इसके बाद न केवल जीर्णोद्धार हुआ, बल्कि दिल्ली विकास प्राधिकरण के अथक प्रयासों के बदौलत मात्र 18 महीनों में इस क्षेत्र का पुनर्निर्माण और कायापलट भी हुआ। दिल्ली में यमुना के बाढ़ के मैदानों के संरक्षक के रूप में डीडीए का वर्णन करते हुए।

32वीं किस्त ट्रांसफर करेंगे सीएम मोहन यादव

भोपाल, (एजेंसी)। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव शुक्रवार को श्लाडली बहना योजनाश की अगली किस्त ट्रांसफर करेंगे। मुख्यमंत्री नर्मदापुरम जिले के माखन नगर में आयोजित एक समारोह में 125 करोड़ से अधिक लाभार्थियों के बैंक खातों में योजना की किस्त भेजेंगे। मध्य प्रदेश सरकार ने गुरुवार को एक बयान में कहा कि राज्य भर में इस योजना के 125 करोड़ से अधिक पात्र लाभार्थियों के खातों में 1,836 करोड़ रुपए से अधिक की राशि हस्तांतरित की जाएगी।इसके अलावा, मुख्यमंत्री गैस सिलेंडर रिफिलिंग सहायता के लिए 29 लाख लाभार्थियों के बैंक खातों में 90 करोड़ रुपए से अधिक की राशि भी ट्रासंफर करेंगे। इस अवसर पर, मुख्यमंत्री यादव नर्मदापुरम जिले के लिए विभिन्न विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और उनका उद्घाटन करेंगे।लाडली बहना योजना के प्रत्येक लाभार्थी को 1,500 रुपए मिलेंगे, क्योंकि पिछले साल नवंबर में इस राशि में 250 रुपए की वृद्धि की गई थी। यह वर्ष 2026 की पहली किस्त होगी और जून 2023 में योजना शुरू होने के बाद से यह 32वीं किस्त होगी। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (वर्तमान में केंद्रीय कृषि मंत्री) के कार्यकाल के दौरान, 2023 के विधानसभा चुनावों से कुछ महीने पहले, इस योजना को 1,000 रुपए की मासिक किस्त के साथ लागू किया गया था।बाद में, सितंबर 2023 में यह राशि बढ़ाकर 1,250 रुपए कर दी गई। मुख्यमंत्री यादव ने पहले कहा था कि 2028 तक यह राशि बढ़ाकर 3,000 रुपये कर दी जाएगी। गौरतलब है कि राज्य में अगले विधानसभा चुनाव 2028 में होंगे।राज्य सरकार के अनुसार, जून 2023 से दिसंबर 2025 तक, इस योजना के तहत लाभार्थियों के खातों में कुल 48,632.70 करोड़ रुपए हस्तांतरित किए जा चुके हैं। जनवरी 2024 से दिसंबर 2025 के बीच ही 38,635.89 करोड़ रुपए का हस्तांतरण किया गया। सरकार ने कहा कि मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना ने राज्य भर की महिलाओं के लिए आर्थिक सुरक्षा, आत्मनिर्भरता और सम्मान सुनिश्चित किया है।

स्टार्टअप इंडिया ने लाखों युवाओं को उद्यम, उद्योग एवं नवाचार के नए अवसर प्रदान किए : योगी आदित्यनाथ

लखनऊ, (संवाददाता)। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 'स्टार्ट अप इंडिया' योजना के 10 वर्ष पूरे होने के मौके पर शुक्रवार को कहा कि पिछले एक दशक में इसने लाखों युवाओं को उद्यम, उद्योग और नवाचार के नए अवसर प्रदान किए हैं। योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर लिखा, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में शुरू की गई 'स्टार्टअप इंडिया' योजना के सफलतम 10 वर्ष पूरे होने पर सभी को हार्दिक बधाई। यह अभिनव पहल युवाओं में उद्यमिता की भावना को बढ़ावा देते हुए भारत को नवाचार संचालित अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में गतिशील बना रही है।'' उन्होंने कहा, '' पिछले एक दशक में स्टार्टअप इंडिया ने लाखों युवाओं को उद्यम, उद्योग एवं नवाचार के नए अवसर प्रदान किए हैं। उत्तर प्रदेश आज देश के अग्रणी स्टार्टअप परिवेश के रूप में तेजी से विकसित हो रहा है। इस विकासोन्मुख अभियान से 'आत्मनिर्भर एवं विकसित भारत' की यात्रा को नई ऊर्जा प्राप्त हो रही है।'' 'स्टार्टअप इंडिया' की शुरुआत 16 जनवरी 2016 को एक परिवर्तनकारी राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में की गई थी जिसका उद्देश्य नवोन्मेष को पोषित करना, उद्यमिता को बढ़ावा देना और निवेश–आधारित वृद्धि को सक्षम बनाना है ताकि भारत को नौकरी तलाशने वालों के बजाय नौकरी देने वालों का देश बनाया जा सके। आधिकारिक बयान के मुताबिक पिछले एक दशक में 'स्टार्टअप इंडिया' पहल भारत की आर्थिक एवं नवोन्मेष संरचना का एक प्रमुख आधार बनकर उभरी है। इसने संस्थागत तंत्र को मजबूत किया है, पूंजी एवं मार्गदर्शन तक पहुंच का विस्तार किया है और स्टार्टअप के लिए विभिन्न क्षेत्रों एवं भौगोलिक क्षेत्रों में विकास तथा विस्तार के अनुकूल माहौल को बढ़ावा दिया है। बयान में कहा गया कि इस दौरान भारत के स्टार्टअप परिवेशी तंत्र में अभूतपूर्व विस्तार देखा गया है और देश र में 2,00,000 से अधिक स्टार्टअप को मान्यता दी गई है।

आतंकवाद की विचारधारा खत्म होने तक जारी रहेगा ऑपरेशन सिंदूर : राजनाथ सिंह

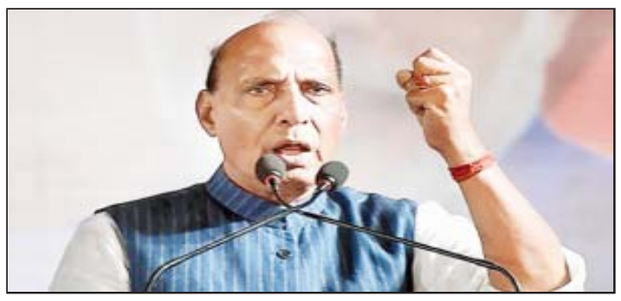

जयपुर, (एजेंसी)। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुवार को जोर देकर कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है और उन्होंने घोषणा की कि आतंकवाद की विचारधारा के पूर्णतः उन्मूलन तक भारत के शांति प्रयास जारी रहेंगे। सेना दिवस के अवसर पर सवाई मान सिंह (एसएमएस) स्टेडियम में आयोजित शौर्य संध्या कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है क्योंकि आतंकवाद की मानसिकता के उन्मूलन तक शांति के लिए हमारा प्रयास जारी रहेगा। मैं यह घोषणा राजस्थान की वीर भूमि से कर रहा हूं।जैसे ही सेना के पैराट्रूपर्स स्टेडियम में उतरे, पूरा स्टेडियम 'जय हो' के नारों से गूंज उठा और रक्षा मंत्री की उपस्थिति में देशभक्ति का माहौल बन गया। राजनाथ सिंह ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से भारत ने न केवल अपनी सैन्य शक्ति का प्रदर्शन किया बल्कि अपने राष्ट्रीय चरित्र को भी प्रदर्शित किया। उन्होंने कहा कि आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई सावधानीपूर्वक योजना बनाकर और मानवीय मूल्यों को ध्यान में रखते हुए की गई थी। इसीलिए ऑपरेशन सिंदूर को न केवल एक सैन्य अभियान के रूप में, बल्कि साहस और संयम के प्रतीक के रूप में याद किया जाएगा।इससे पहले दिन में, जयपुर में सैन्य शक्ति का भव्य प्रदर्शन देखने को मिला जब ब्रह्मोस मिसाइलें, भीष्म और अर्जुन टैंक, पिनाका रॉकेट लॉन्चर, रोबोटिक डॉग्स और अन्य उन्नत उपकरण सड़कों पर निकले। अपैची हमलावर हेलीकॉप्टरों ने हवाई करतब दिखाए, जबकि जगुआर लड़ाकू विमानों ने नल (बीकानेर) हवाई अड्डे से उड़ान भरी, जिसे देखने के लिए भारी भीड़ उमड़ी। पहली बार, सेना दिवस परेड किसी सैन्य छावनी के बाहर आयोजित की गई, जिसमें हजारों नागरिक इस ऐतिहासिक आयोजन को देखने के लिए जगतपुरा के महल रोड पर जमा हुए। परेड की शुरुआत ऑपरेशन सिंदूर में शहीद हुए सैनिकों को सेना पदक (वीरता) प्रदान करने के साथ हुई।

भाजपा ने निकाय चुनाव के जनादेश पर खुशी जताई, शिवाजी की सेना के आगे बढ़ने से की तुलना

मुंबई, (एजेंसी)। महाराष्ट्र में बृहन्मुंबई महानगरपालिका समेत 20 नगर निकायों में चुनाव संपन्न कराए जाने के बाद आज जनादेश आया। भाजपा नेताओं के मुताबिक ये ऐतिहासिक चुनाव परिणाम हैं। पार्टी की उल्लेखनीय सफलता पर भाजपा के राज्यसभा सांसद और पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा, पहले बिहार में हमें सफलता मिली। त्रिवेदी ने कहा कि इसके बाद केरल में भी भाजपा को कामयाबी मिली। अब महाराष्ट्र के नगर निगम में ये अभूतपूर्व सफलता निश्चित रूप से भविष्य के लिए शुभ संकेत है। नकारात्मक राजनीति करने वाले लोगों को राज्य की जनता के करारा जवाब दिया है। भाजपा सांसद ने आगे कहा कि महाराष्ट्र की भाषा में कहते हैं जय–जय महाराष्ट्र माझा। आज महाराष्ट्र की जनता ने हमें जो समर्थन दिया है, इसके लिए विनम्रता से आभार... ये छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमि है.. . जैसे शिवाजी की चतुरंगिणी सेना मन में उमंग धारण करके चलती थी, वैसे ही देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में भाजपा आगे बढ़ रही है। भाजपा महासचिव तरुण चुघ ने महाराष्ट्र में भाजपा गठबंधन के शनदार प्रदर्शन पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि भारत की जनता बहुत समझदार है। पहाड़ से सागर तक, भारत का कोई भी हिस्सा हो, जनता हर जगह कांग्रेस पार्टी और इंडी गठबंधन को सजा दे रही है। राहुल जी, आईना साफ मत करिए। आईना साफ करने से मुंह पर लगे कालिख के निशान मिट नहीं सकते। चुघ ने आगे कहा कि आप हार का ठीकरा दूसरों पर फोड़ने की कोशिश कर रहे हैं,।

भाजपा सरकार ने प्रशासन का दुरुपयोग कर मतदाता सूचियों में हेराफेरी का षड्यंत्र रचा : अशोक गहलोत

नई दिल्ली, (एजेंसी)। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार पर प्रशासन का दुरुपयोग कर मतदाता सूचियों में हेराफेरी का षड्यंत्र रचने का बृहस्पतिवार को आरोप लगाया। गहलोत ने इसे शर्मनाक बताते हुए कहा कि इसने भाजपा को ''बेनकाब'' कर दिया है। गहलोत ने कहा, "आज का दिन राजस्थान में लोकतंत्र के लिए एक काले अध्याय जैसा है, जिसने भाजपा को बेनकाब कर दिया है। सत्ता के मद में चूर भाजपा सरकार ने प्रशासन का दुरुपयोग कर मतदाता सूचियों में हेराफेरी का जो षड्यंत्र रचा है, वह शर्मनाक है।" कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने दावा किया कि मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) प्रक्रिया के अंतिम दिन एक सुनियोजित साजिश के तहत निर्वाचन पंजीकरण अधिकारियों (ईआरओ) के माध्यम से बूथ लेवल अधिकारियों (बीएलओ) पर दबाव डाला गया कि वे कांग्रेस विचारधारा वाले मतदाताओं के नाम काटें। उन्होंने आरोप लगाया कि यहां तक कि फॉर्म–सात में पहले से डेटा भरकर बीएलओ को सौंपा गया, जो निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया पर सीधा हमला है। उन्होंने कहा, "कई जगहों पर प्रशासनिक अधिकारियों और बीएलओ ने इस लोकतंत्र की हत्या में शामिल होने से इनकार किया, तो सत्ताधारी पार्टी के लोगों ने उन्हें तबादलों की धमकी दी। पूर्व मुख्यमंत्री ने एक बयान में कहा, "भाजपा ने ऐसा दुस्साहस कर जनता और लोकतंत्र का अपमान किया है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र सरदारपुरा तक में ऐसा कुप्रयास किया गया है। मैंने इस संबंध में राज्य निर्वाचन आयुक्त नवीन महाजन से फोन पर बात कर जानकारी दी है और त्वरित कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने निर्वाचन कार्य में लगे अधिकारियों से संवैधानिक मर्यादा का पालन करने की अपील की। गहलोत ने कहा, "मैं उन अधिकारियों को भी स्पष्ट शब्दों में आगाह करना चाहता हूं जो भाजपा के दबाव में संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। समय बदलते देर नहीं लगती। सरकारें आती–जाती रहेंगी, लेकिन यदि आपने नियम विरुद्ध कार्य किया।

जनता को भ्रमित कर रहा आयोग, वोट चोरी देशविरोधी : राहुल गांधी

मुंबई , (एजेंसी)। एक तरफ महाराष्ट्र में बीएमसी समेत 29 निगमों को लेकर चल रही मतगणना के शुरुआती रुझानों में भाजपा को बड़ी बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं दूसरी ओर अब लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर जनता को भ्रमित करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग जनता को गुमराह कर रहा है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर किए गए पोस्ट में कुछ अखबारों का स्क्रीनशॉट साझा किया। इसमें गुरुवार को नगर निगम चुनाव के मतदान के दौरान वोट डालने के बाद उंगली पर लगाई जा रही स्याही मिटाने के मामले को उठाया। राहुल गांधी ने इसे लोकतंत्र में भरोसे की गिरावट बताया। साथ ही कहा कि चुनाव आयोग द्वारा जनता को भ्रमित करना हमारे लोकतंत्र में भरोसे की कमी का कारण है। उन्होंने अंत में जोर देते हुए रहा कि वोट चोरी एक देश विरोधी काम है। बीते गुरुवार बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) समेत महाराष्ट्र के 29 नगर निगमों पर मतदान के बाद उंगली पर लगी स्याही को मिटाने के दावे और वायरल वीडियो ने नया विवाद खड़ा कर दिया। आरोप–प्रत्यारोप की राजनीति तेज हुई, चुनाव आयोग ने स्पष्टीकरण भी दिया। सबसे पहले इस मामले में राज्य के मंत्री और शिंदे गुट के शिवसेना नेता संजय शिरसाट ने गुरुवार को दावा किया था कि यह स्याही आसानी से मिट रही है, जिससे फर्जी मतदान की आशंका पैदा हो सकती है। इसके बाद महाराष्ट्र राज्य चुनाव आयोग ने को स्पष्ट किया था कि मतदाता की अंगुली पर लगाई गई इंडलेबल इंक को मिटाने या पोलिंग के दौरान भ्रम फैलाने का प्रयास करना चुनावी गड़बड़ी माना जाएगा। राज्य चुनाव आयोग ने मतदाताओं और सभी दलों को साफ–साफ चेतावनी दी है कि नियमों का उल्लंघन करना गंभीर अपराध है और किसी भी परिस्थिति में दोबारा वोटिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी।

संपादकीय

संवैधानिक व्यवस्था दायरे में नहीं

कोलकाता की घटना संघीय ढांचे के चरमराने का संकेत है। संबंधित पक्ष ऐसे विवादों से सड़कों पर निपटने लगें, तो उसका अर्थ है कि बात संवैधानिक व्यवस्था के दायरे में नहीं रह गई है। आखिर इस तरह की नौबत क्यों आई? कोलकाता में आई–पैक के दफ्तर पर प्रवर्तन निदेशालय के छापे का मुकाबला मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सड़क पर उतर कर किया। ऐसा शायद पहली बार हुआ, जब एक केंद्रीय एजेंसी की कार्रवाई के बीच किसी मुख्यमंत्री ने इस तरह का दखल दिया हो। उस घटना के बाद से ममता बनर्जी और उनकी पार्टी ने इसको लेकर एक बड़ा राजनीतिक अभियान छेड़ रखा है। उधर ईडी ने सुप्रीम कोर्ट की पनाह ली है। ईडी का इल्जाम है कि आई–पैक एजेंसी से जुड़े व्यक्तियों ने हवाला के जरिए अवैध रूप से धन का लेन–देन किया है। जबकि तृणमूल कांग्रेस का आरोप है कि चूंकि आई–पैक को उसने अपने विधानसभा चुनाव अभियान के प्रबंधन का ठेका दिया है और इसलिए उसके पास पार्टी की रणनीति संबंधी आंकड़े हैं, तो उन्हें ही चुराने ईडी वहां गई थी। तृणमूल की शिकायत पर कोलकाता पुलिस ने दस्तावेजों की चोरी का केस दर्ज किया है। उसने उन ईडी तथा केंद्रीय शस्त्र बल के कर्मियों की पहचान शुरू कर दी है, जो आई–पैक के दफ्तर पर गए। तो इस रूप में ये मामला केंद्र और राज्य सरकारों के बीच टकराव में तब्दील हो गया है। यह भी उल्लेखनीय है कि तृणमूल ने अपनी शिकायत को बयानों या कानूनी चुनौती तक सीमित नहीं रखा। उसकी नेता एवं मुख्यमंत्री ने प्रत्यक्ष हस्तक्षेप से ईडी के छापे में रुकावट डाली। यह घटना देश के संघीय ढांचे के चरमराने का संकेत है। संबंधित पक्ष ऐसे विवादों से सड़कों पर निपटने लगें, तो उसका अर्थ है कि बात संवैधानिक व्यवस्था के दायरे में नहीं रह गई है। यह गंभीर विचार–विमर्श का विषय है कि ये नौबत क्यों आई? साफ वजह राजनीतिक वर्ग में आपसी भरोसे का टूट जाना है। विपक्षी खेमों में आम धारणा है कि केंद्रीय एजेंसियां सत्ताधारी भाजपा के सियासी मकसद को साधने का औजार बन गई हैं। इस दौर में कानूनों की व्याख्या के क्रम में न्यायपालिका ने भी राजनीतिक परिदृश्य की अनदेखी कर तकनीकी नजरिया अपना रखा है। ऐसे में तृणमूल को सड़क पर मुकाबला करना मुफीद महसूस हुआ होगा। लेकिन लोकतंत्र एवं संघीय व्यवस्था के लिए यह अच्छा संकेत नहीं है।

पीड़ितों का शास्त्र न बन जाए उमर-शरजील की हिरासत

उमेश

छह साल पहले राजधानी दिल्ली के उत्तरी–पूर्वी हिस्से के जाफराबाद और मौजपुर में हुए दंगों पर राजनीति थम नहीं रही है। राजनीति तब भी खूब हुई, जब 23 फरवरी 26 फरवरी 2020 के बीच हुए दंगों का घाव बिल्कुल हरा था। इस बार इन दंगों पर राजनीति की वजह पांच जनवरी को सुप्रीम कोर्ट से आया एक आदेश है, जिसमें इन दंगों के पांच आरोपियों गुलफिशां फातिमा, मीरान हैदर, शिफा उर रहमान, शादाब अहम और मोहम्मद सलीम खान को जमानत दे दी गई है। इस आदेश को लेकर राजनीति ही नहीं हो रही, प्रकारांतर से देश की सबसे बड़ी अदालत भी निशाने पर है। सर्वोच्च अदालत ने इन दंगों के आरोपी शरजील इमाम उमर खालिद को जमानत देने से साफ इनकार कर दिया। इस फैसले के खिलाफ सोशल मीडिया पर इन दोनों आरोपियों के पक्ष और सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के खिलाफ बयानबाजी तेज हो गई। मनमोहन सिंह की सत्ता और कांग्रेस के आंख के तारे रहे जेएनयू के पूर्व छात्र रहे एक बड़े पत्रकार ने इन दोनों आरोपियों को देश का प्रखर बुद्धिजीवी बताते हुए उन्हें जमानत ना दिए जाने पर आश्चर्य जताया। वामपंथी वैचारिकी की एक खासियत है। वह अपने पक्ष में अकादमिक तर्क गढ़ने में माहिर रही है। अपने लिहाज के तथ्यों को चुनकर उसके हिसाब से वह तर्क गढ़ने और अपने पक्ष में माहौल बनाने के साथ ही अपनी वैचारिकी के लोगों को पीड़ित दिखाने में वह हमेशा आगे रहती रही है। शरजील इमाम और उमर खालिद के पक्ष में वामपंथी वैचारिकी उसी तरह से उमड़ पड़ी है। वह दोनों के बारे में यह राय बनाने की भरपूर और प्रभावी कोशिश कर रही है कि दोनों दंगाई नहीं, दंगे के शातिर षड्यंत्रकारी नहीं, बल्कि वे प्रखर बुद्धिजीवी हैं। वामपंथी वैचारिकी यह साबित करने की भी कोशिश कर रही है कि दोनों चूंकि अल्पसंख्यक यानी मुस्लिम समुदाय से हैं, और चूंकि केंद्र में हिंदुत्ववादी सत्ता है। इसलिए अल्पसंख्यक बुद्धिजीवियों को दबाया और प्रताड़ित किया जा रहा है। वामपंथी वैचारिकी और उसकी बुद्धिजीवी जमात यह विमर्श खड़ा करने की कोशिश कर रही है कि हिंदुत्ववादी सत्ता के इशारे पर अदालत मुस्लिम समुदाय के निर्दोष बुद्धिजीवियों को बलि का बकरा बना रही है। यह विमर्श खड़ा करके वामपंथी वैचारिकी और उसकी बुद्धिजीवी जमात दरअसल दंगाईयों को पीड़ित के तौर पर स्थापित करने की कोशिश कर रही है। दिलचस्प यह है कि उमर खालिद और शरजील इमाम की जमानत को नकारने के लिए जहां सर्वोच्च न्यायालय को निशाना बनाया जा रहा है, वहीं बाकी पांच आरोपियों को जमानत दिए जाने के आदेश को जबरदस्ती नेपथ्य में धकेलने की कोशिश की जा रही है। दो लोगों को जमानत ना मिलने को, पांच लोगों को जमानत मिलने की प्रक्रिया के सामने पक्षपाती दिखाया जा रहा है। पांच आरोपियों को मिली जमानत को यह दिखाने की कोशिश हो रही है कि ऐसा करके सर्वोच्च अदालत ने कोई एहसान नहीं किया है। वामपंथी वैचारिकी के इस विमर्श का पूरा मकसद यह भुलाना है कि 2020 के दिल्ली दंगे हिंदू–मुस्लिम दंगे नहीं थे। इस विमर्श का लक्ष्य यह भी भुलाना है कि इन दंगों में अधिसंख्य हिंदू समुदाय के लोग मारे गए थे। इस विमर्श का यह भी मकसद है कि इन दंगों के दौरान आईबी के मासूम अधिकारी अंकित शर्मा की हुई हत्या को सामान्य अपराध दिखाने की कोशिश हो रही है। इन दंगों में आधिकारिक रूप से 53 लोग मारे गए थे। दंगा खत्म होने के बाद कई लाशें नाले में बहती मिलीं। जिस तरह उस दौरान दंगे के एक आरोपी आम आदमी पार्टी के तत्कालीन पार्षद ताहिर हुसैन के घर पत्थर, हथियार और बड़ी–सी गुलेल मिली, उससे तो यही साबित होता है कि दिल्ली के ये दंगे हिंदू समाज को सबक सिखाने की मुस्लिम समाज के कुछ दंगाइयों की कोशिश थी। इन दंगों की टाइमिंग को भी भुलाना आसान नहीं है। जब ये दंगे हुए थे, उसके कुछ ही दिन बाद अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति डोनॉल्ड ट्रंप का भारत दौरा हुआ था। इन दंगों के जरिए कोशिश यह भी की गई थी कि दंगा के षड्यंत्रकारियों का मकसद ट्रंप की भारत यात्रा को निरस्त कराना, भारतीय राज व्यवस्था को बदनाम करना और इसके जरिए भारत की छवि को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नुकसान पहुंचाना था। इसमें किंचित वे कामयाब भी हुए। शरजील इमाम और उमर खालिद के पक्ष में उठती आवाजों का प्रतिकार भी जरूरी है। इन आवाजों की पोल खोलना भी जरूरी है। राष्ट्रवादी धारा के प्रबुद्धजन वामपंथी विमर्श के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं, लेकिन जिस तरह कभी वामपंथी वैचारिकी के अगुआओं को देश की मौजूदा व्यवस्था में राजकीय तवज्जो मिल रहा है, उससे प्रखर राष्ट्रवादी वैचारिकी किंचित परेशान भी है और दुखी भी। इसलिए जैसा इस वामपंथी विमर्श का प्रतिकार होना चाहिए, उस स्तर का प्रतिकार नहीं हो पा रहा है। यह तो भला हो कि हिंदुत्ववादी मानस इन दिनों बेहद सचेत हो चुका है। निश्चित तौर पर इसकी वजह मुस्लिम तुष्टिकरण की हकीकत का सामने आना तो है ही, केंद्रीय सत्ता में मोदी की अगुआई में हिंदुत्वादी ताकतों का प्रभावी बनना भी है। दिल्ली दंगों को लेकर नए विमर्श गढ़ने की कोशिशें होती रहेंगी। जरूरत यह है कि इसका लगातार उचित प्रतिकार तो होते ही रहे, हिंदुत्व विरोधी नैरेटिव के खिलाफ आक्रामक राष्ट्रवादी विमर्श लगातार उठता रहे। इसी अंदाज में होना यह चाहिए कि दिल्ली दंगों को लेकर बार–बार यह कहा जाना चाहिए कि ये हिंदुओं के खिलाफ खुराफाती और शांति विरोधी मुस्लिम सिरफिरों के सुनियोजित अपराध थे। जिसमें 53 लोगों की मौत हुई। इनमें ज्यादातर हिंदु थे। दो सौ से ज्यादा लोग घायल हुए। यह भी बताने की कोशिश होनी चाहिए कि घायलों में भी ज्यादातर हिंदू ही थे। इसकी भी बार–बार चर्चा होनी चाहिए कि इन दंगों में सिर्फ और सिर्फ हिंदू समुदाय की ही दुकानों और हिंदू समुदाय के ही मकानों को लक्ष्य बनाकर नुकसान पहुंचाया गया। यह भी बताने की कोशिश लगातार जारी रहनी चाहिए कि इन दंगों का एक मकसद तत्कालीन नागरिकता संबंधी कानून में संसद द्वारा किया गया संसोधन भी था। नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ जारी दुष्प्रचार भी था। लगातार ऐसा जवाबी विमर्श खड़ा होता रहा तो मुस्लिम समुदाय के शांति विरोधी और अपराधी और दंगाई समर्थक वर्ग की मंशा का खुलासा करना आसान होगा। लगातार जारी ऐसे विमर्श की वजह से हिंदुत्व विरोधी ताकतें जहां एक्सपोज होंगी, वहीं उनके खिलाफ आम मानस उठ खड़ा होगा। अल्पसंख्यक तुष्टिकरण के जरिए अपनी राजनीतिक रोटियां सेंकने वाली राजनीतिक धाराएं भी इससे एक्सपोज होंगी। इस प्रक्रिया के लगातार जारी रहने के चलते एक दौर ऐसा भी आएगा, जब छद्म विमर्शकारों के सामने सच को पूरी हकीकत के साथ स्वीकार करने के लिए मजबूर होना पडेगा। फिलहाल यह जान लेना चाहिए कि जिन पांच आरोपियो को सर्वोच्च अदालत ने जमानत दी है, उन्हें दो–दो लाख के निजी मुचलके पर रिहा किया गया है।

अमेरिकी व्यवस्था का कोई तोड़ नहीं

हरिशंकर व्यास

यह तारीफ नहीं है। वह सत्यमेव जयते है, जिसका आधार बुद्धि–ज्ञान और सैन्य शक्ति, दोनों के एवरेस्ट की वाह है। अमेरिका ने सन् 2025द26 में दिमाग से कृत्रिम बुद्धि को स्थापित कर जहां मानवता को चमत्कृत किया, वहीं तीन जनवरी 2026 की रात में उसके सैन्य बल ने वेनेजुएला देश के राष्ट्रपति को उठा कर विश्व को चौंकाया। व्यर्थ है इसके लिए डोनाल्ड ट्रंप को श्धुरंधरस्य बताना। असल सत्य ढाई सौ साल पुराने अमेरिका के उस संविधान, उस व्यवस्था का है, जिसमें असंभव को संभव बनाने का डीएनए व्यक्तिगत स्वतंत्रता के सांचे की धुन में निहित है। यह व्यवस्था की वह बुनावट है, जिसमें हर व्यक्ति असंभव को संभव बनाने के अवसर को खोजता है, लपकता है और उसमें अपने को खपाता है। भारत में हम लोग व्यक्तियों, चेहरों यानी राष्ट्रपतियों, नेताओं को ताकते हैं, जबकि धुरंधरी व्यवस्था से बनती है। सिस्टम से उत्प्रेरित व्यक्तिगत मानसिकता, वृत्ति और आचरण से ही फिर अर्थ (पूंजीवाद, नवाचार, तकनीक, वित्तीय धुरी), काम (इच्छा, व्यक्तिगत भोग, उपभोक्तावाद, प्रतिस्पर्धा, जुनून, विलासिता) तथा धर्म की सार्वभौमिक, सेक्युलर समझ पैठती है। निश्चित ही खांटी अमेरिकी लोग परलोक, जन्म–जन्मांतर या मोक्ष–मुक्ति की धारणाओं में नहीं जीते हैं। वे वर्तमान के सत्य में जीते हैं। वहां के नागरिक अंधविश्वासों, टोने–टोटकों, भक्ति और झूठ से लगभग मुक्त हैं। वे अतीत में नहीं, आधुनिकता में आगे बढ़ते जाने के लिए सतत हाथ–पांव मारते हैं। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिका में भी वही है, जो जॉर्ज डब्ल्यू बुश, बराक ओबामा या राष्ट्रपति आइजनहावर और उनके विदेश मंत्री जॉन फोस्टर डलेस के डोनरो डॉक्ट्रिन के शक्ति–सूत्र में था। वेनेजुएला के ताजा प्रकरण में मुझे राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की कद–काठी, भाव–भंगिमा, बड़बोलेपन से बार–बार सद्दाम हुसैन, कर्नल गद्दाफी, ओसामा बिन लादेन, इस्लामिक स्टेट के बगदादी आदि वे चेहरे याद होते हैं, जो कथित शक्ति, क्रूरता, बर्बरता के सूरमा–भोपाली थे (इतिहास में एक नाम हिटलर भी है)। ये सब किसके शिकार हुए? अमेरिकी सैन्य ऑपरेशनों के। सही है कि इस काम में रिपब्लिकन पार्टी के राष्ट्रपतियों की संख्या अधिक है, मगर डेमोक्रेटिक पार्टी के राष्ट्रपतियों ने भी संकोच नहीं किया। राष्ट्रपति बराक ओबामा ने ट्रंप के ताजा श्ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व्य की तरह ही श्ऑपरेशन नेप्च्यून स्पीयरस्य को हरी झंडी दी थी। पाकिस्तान के एबटाबाद में अमेरिका की नेवी सील टीम ने 9ध11 हमलों के मास्टरमाइंड ओसामा को 1दृ2 मई 2011 की रात में मारने के ऑपरेशन को वैसे ही अंजाम दिया, जैसे इस तीन जनवरी की आधी रात को काराकास के राष्ट्रपति भवन में निकोलस मादुरो को दबोचने का सैन्य अभियान हुआ। सो, ओबामा हों या डोनाल्ड ट्रंप, ये उस अमेरिकी व्यवस्था के प्रतिनिधि हैं, जिसमें ओलंपिक मेडल जीतना सामान्य बात है, तो सिलिकॉन वैली में कृत्रिम बुद्धि (एआई) की रचना का प्रतिमान भी सामान्य हैय तो नौसेना की नेवी सील टीम हो या डेल्टा फोर्स या सीआईए, सभी अपनी क्षमताओं का वह जज्बा लिए होते हैं, जो वेयक्तिक धुन, टीम में पकती है और फिर बस उद्देश्य व कमांड की जरूरत होती है। ऐसे जज्बे वाले दूसरे देश का नाम इजराइल है। इजराइल की वजह यहूदियों का इतिहास–बोध और संकल्प है। इजराइल ने 1948 में गठन के बाद से व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बूते ही अर्थ, धर्म, काम की मनुष्य–वृत्तियों में नागरिकों और व्यवस्था को ऐसा बनाया है कि प्रधानमंत्री कोई हो, वह ज्ञात खतरों के प्रति कभी लापरवाह नहीं होता। इजराइली व्यवस्था भी चेक–बैलेंस में पाबंद है। नेतन्याहू हों या कोई प्रधानमंत्री, वे संस्थाओं और व्यवस्थाओं की स्वतंत्रता, जीवंतता का गला नहीं घोंटते। तभी ये दो ही देश हैं, जो विश्व राजनीति में बतौर धुरंधर बाकी सभी देशों को ठेंगा दिखाते हैं। ये जो चाहते हैं, वह करते हैं, फिर भले कोई इसे दादागीरी कहे या गुंडागर्दी! सन् 2025 की जनवरी से इस तीन जनवरी की ताजा घटना में डोनाल्ड ट्रंप की पहचान मनमजी की है। इससे अमेरिकी पहचान बिगड़ी, तो अमेरिका में भी आर–पार की राजनीति के पाले बने हैं। मगर अमेरिका के हित की कसौटी में गौर करें, तो ट्रंप के फैसले अर्थिकी, सैन्य क्षमता, उद्यमशीलता, सामाजिक संरचना, पूंजीवाद आदि, सभी कसौटियों में ठीक ही हैं। भाषा और तौर–तरीकों का फर्क हैय अन्यथा राष्ट्रहित में उनके वैश्विक फैसलों (टैरिफ जंग, चीन को कसना, यूरोपीय देशों के सुरक्षा–खर्च का बोझ घटाना, अपने से सटे दक्षिण अमेरिकी देशों यानी पश्चिमी गोलार्ध में अमेरिकी वर्चस्व की दादागीरी पर क्यों अमेरिका में कोई आपत्ति करेगा? वेनेजुएला के तानाशाह राष्ट्रपति को उठवाने के बाद ट्रंप ने कहा है, अब से पश्चिमी गोलार्ध में अमेरिकी वर्चस्व पर फिर कभी सवाल नहीं उठेगा। अमेरिका बहुत लंबे समय से श्मुनरो डॉक्ट्रिनय पर अमल के प्रति लापरवाह था। अब से ऐसा नहीं होगा। ध्यान रहे, श्मुनरो डॉक्ट्रिनय का उद्देश्य लैटिन अमेरिका से विदेशी शक्तियों को बाहर रखना है। मतलब पूंजीवादी अमेरिका को अपने पिछवाड़े या पड़ोस में सोवियत संघ, रूस, वामपंथियों का प्रभाव बर्दाश्त नहीं।

बचत और खर्च का असंतुलन: नये भारत के लिए बड़ी चुनौती

ललित

महामारी के बाद की दुनिया केवल स्वास्थ्य के स्तर पर ही नहीं, बल्कि आर्थिक सोच और व्यवहार में भी एक बड़े संक्रमण से गुजरी है। वैश्विक आपूर्ति शृंखलाओं की अस्थिरता, भू–राजनीतिक तनाव, बढ़ती महंगाई, तकनीक–आधारित बाजार और उपभोक्तावादी संस्कृति के तीव्र प्रसार ने लोगों की खर्च करने की प्रवृत्ति को असाधारण रूप से बढ़ा दिया है। इस बदलाव का सबसे गहरा असर घरेलू बचत पर पड़ा है। भारत सहित अनेक देशों में घरेलू बचत दरें ऐतिहासिक रूप से निचले स्तर पर पहुंच चुकी हैं। उपभोग बढ़ रहा है, लेकिन भविष्य की सुरक्षा के लिए आवश्यक बचत निरंतर घटती जा रही है। यह स्थिति केवल आर्थिक नहीं, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक चिंता का विषय भी बनती जा रही है। भारत जैसी उभरती अर्थव्यवस्था के लिए घरेलू बचत सदैव विकास की रीढ़ रही है। बुनियादी ढांचे से लेकर औद्योगिक निवेश तक, भारत की विकास गाथा में घरेलू बचत की भूमिका निर्णायक रही है। परंतु आज स्थिति यह है कि विशेषकर युवा पीढ़ी में बचत की दर 10 से 15 प्रतिशत तक सिमट गई है। यह आंकड़ा किसी भी उभरती अर्थव्यवस्था के लिए संतोषजनक नहीं कहा जा सकता। जब भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है, तब बचत और खर्च के बीच असंतुलन एक गंभीर चेतावनी के रूप में सामने आ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने में युवाओं की भूमिका को हमेशा निर्णायक माना है और वे बार–बार यह संदेश देते रहे हैं कि बचत केवल व्यक्तिगत सुरक्षा नहीं, बल्कि राष्ट्र निर्माण की नींव है। उनके अनुसार उपभोग से पहले बचत की संस्कृति युवाओं में आत्मनिर्भरता, अनुशासन और दीर्घकालिक सोच का विकास करती है। जन–धन योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, अटल पेंशन योजना, डिजिटल बचत और निवेश के माध्यमों को प्रोत्साहित करते हुए उन्होंने यह स्पष्ट किया है कि छोटे–छोटे नियमित निवेश भविष्य की बड़ी आर्थिक शक्ति बनते हैं। मोदी का विचार है कि जब युवा वर्ग आज अनावश्यक खर्च से बचकर बचत और उत्पादक निवेश की ओर अग्रसर होगा, तभी भारत की अर्थव्यवस्था स्थिर, समावेशी और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बन सकेगीय क्योंकि आत्मनिर्भर युवा ही सशक्त भारत की सबसे बड़ी पूंजी है। भारतीय परंपरा में बचत को केवल आर्थिक क्रिया नहीं, बल्कि एक सद्गुण माना गया है। "आज की बचत, कल का संबल" जैसी कहावतें हमारे सामाजिक व्यवहार का हिस्सा रही हैं। गृहस्थ जीवन में संतुलन, संयम और संचय को जीवन–मूल्य के रूप में स्वीकार किया गया। बच्चों की गुल्लक, अनाज के कोठार, गहनों के रूप में सुरक्षित धन, और त्योहारों पर सीमित व सादगीपूर्ण खर्च–ये सब भारतीय जीवनशैली के अभिन्न अंग थे। संकट के समय भारतीय परिवार किसी के सामने हाथ फैलाने की बजाय अपनी जमा पूंजी और संसाधनों पर भरोसा करता था। यह आत्मनिर्भरता भारतीय समाज की शक्ति रही है। लेकिन बदलती जीवनशैली और बाजार–प्रेरित संस्कृति ने इस परंपरा को कमजोर किया है। आज 'जियो अभी' की मानसिकता, आसान कर्ज, ईएमआई संस्कृति, क्रेडिट कार्ड, ऑनलाइन शॉपिंग और सोशल मीडिया पर दिखावे की प्रतिस्पर्धा ने खर्च को एक प्रकार की पहचान बना दिया है। उपभोग अब आवश्यकता से अधिक आकांक्षा से संचालित होने लगा है। अनुभवों, ब्रांड और त्वरित संतुष्टि को प्राथमिकता देने से दीर्घकालीन वित्तीय सुरक्षा पीछे छूटती जा रही है। विशेषकर जेन–जी और युवा मिलेनियल पीढ़ी के लिए बचत एक बोझ या भविष्य की अस्पष्ट चिंता जैसी प्रतीत होने लगी है। यह स्थिति भारतीय दर्शन की मूल भावना के विपरीत है। भारतीय विचार परंपरा न अति भोग की पक्षधर है, न अति त्याग की। संयम, संतुलन और विवेक का मार्ग ही श्रेष्ठ माना गया है। यही सिद्धांत आर्थिक जीवन में भी लागू होता है। उपभोग आवश्यक है, क्योंकि इससे अर्थव्यवस्था गतिशील रहती है, रोजगार सृजन होता है और नवाचार को प्रोत्साहन मिलता है। परंतु जब खर्च अनियंत्रित हो जाए और बचत उपेक्षित हो जाए, तब व्यक्ति ही नहीं, समाज और राष्ट्र भी असुरक्षित हो जाते हैं। अनुभवों, ब्रांड और त्वरित संतुष्टि को प्राथमिकता देने से दीर्घकालीन वित्तीय सुरक्षा पीछे छूट रही है। भारतीय आर्थिक सोच में बचत को आर्थिक सुरक्षा और विकास का आधार माना जाता है, जहाँ घर–परिवार की आय का एक बड़ा हिस्सा (लगभग 70 प्रतिशत) घरेलू बचत से आता है, जो सोने, स्थायी जमा और पीपीएफ जैसी योजनाओं में होता है, लेकिन नई पीढ़ी में 'खर्च करो' की सोच बढ़ी है, जिससे बचत की दरें घट रही हैं, जबकि वित्तीय साक्षरता और सरकारी योजनाओं (पीपीएफ, एनएससी, सुकन्या समृद्धि) के जरिए इसे फिर से बढ़ाने पर जोर है, क्योंकि बचत से ही निवेश और आर्थिक विकास संभव है। आज की वैश्विक परिस्थितियां इस असुरक्षा को और गहरा कर रही हैं। भू–राजनीतिक तनाव, युद्ध, जलवायु संकट, तकनीकी बदलाव और रोजगार की अनिश्चितता यह संकेत देती है कि भविष्य पहले से

अधिक अस्थिर है। ऐसी स्थिति में बचत और निवेश दोनों की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। यदि भारतीय समाज अपनी बचत संस्कृति से दूर होता गया, तो दीर्घकाल में आर्थिक आत्मनिर्भरता कमजोर पड़ सकती है। विदेशी पूंजी पर निर्भरता बढ़ेगी और घरेलू संसाधनों की भूमिका सीमित होती जाएगी। युवाओं को वित्तीय साक्षरता के माध्यम से बचत और निवेश का महत्व समझाना होगा। यह भी ध्यान देने योग्य है कि बचत में गिरावट का सीधा प्रभाव पारिवारिक एवं सामाजिक सुरक्षा पर पड़ता है। भारत में अभी भी व्यापक सामाजिक सुरक्षा तंत्र सीमित है। पेंशन, स्वास्थ्य बीमा और बेरोजगारी सहायता जैसी व्यवस्थाएं पूरी आबादी को नहीं कवर करतीं। ऐसे में व्यक्तिगत और पारिवारिक बचत ही संकट के समय सहारा बनती है। यदि बचत घटती रही, तो आर्थिक झटकों का असर अधिक विनाशकारी होगा। समस्या केवल युवाओं की मानसिकता तक सीमित नहीं है। वित्तीय साक्षरता की कमी भी इसका एक बड़ा कारण है। आज भी बड़ी संख्या में युवा यह नहीं समझ पाते कि बचत और निवेश में अंतर क्या है, महंगाई का असर कैसे पड़ता है, और छोटी–छोटी नियमित बचत किस प्रकार दीर्घकाल में बड़ा संबल बन सकती है। तकनीक का उपयोग यदि उपभोग बढ़ाने में हो रहा है, तो उसी तकनीक का उपयोग बचत और निवेश को सरल और आकर्षक बनाने में भी किया जा सकता है। डिजिटल प्लेटफॉर्म, माइक्रो–सेविंग्स, स्वचालित निवेश योजनाएं और वित्तीय शिक्षा ऐप्स इस दिशा में प्रभावी भूमिका निभा सकते हैं।

अजीत डोभाल की बदला लेने की बात में अन्तर्निहित खतरनाक परिणाम का भय

डॉ. अरुण

मित्रा हम अच्छी तरह जानते हैं कि हिंसा के कई नतीजे होते हैं। इसका असर शारीरिक घटनाओं के होने से पहले ही शुरू हो जाता है, जो मानसिक स्वास्थ्य संकट के रूप में सामने आता है। इंसानी सेहत पर शारीरिक असर जल्द ही चोट, विकलांगता और मौत के रूप में देखा जा सकता है। आर्थिक गतिविधि और शिक्षा कार्यक्रम भी बुरी तरह प्रभावित होते हैं। उलटी–सीधी बातों से भरे एक भाषण में, भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने, एक बारीक लेकिन साफ तरीके से, युवाओं से बदला लेने का विचार अपनाने को कहा है। 10 जनवरी 2026 को विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग में लगभग 3,000 युवाओं की एक सभा को संबोधित करते हुए, उन्होंने कहा कि हालांकि बदला श्एक अच्छा शब्द नहीं है,श फिर भी यह श्एक बहुत बड़ी ताकतश हो सकता है। उन्होंने दर्शकों से इतिहास का बदला लेने और देश को एक बार फिर महानता की ओर ले जाने का आग्रह किया– न केवल सीमा सुरक्षा के मामले में, बल्कि अर्थव्यवस्था, सामाजिक विकास और हर दूसरे क्षेत्र में भी।सोमनाथ मंदिर का चुपचाप जिक्र करते हुए, उन्होंने

आगे कहा कि भारत ने पहले बहुत कुछ झेला है और उसे हमलों और गुलामी के दर्दनाक इतिहास का श्बदलाश लेना चाहिए। उन्होंने मजबूत नेतृत्व की जरूरत पर भी जोर दिया, और खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिक्र किया। अपनी बात को मजबूत करने के लिए, उन्होंने नेपोलियन को उद्धृत कियारू श्मैं एक भेड़ के नेतृत्व में 1,000 शेरों से नहीं डरता, लेकिन मैं एक शेर के नेतृत्व में 1,000 भेड़ों से डरता हूं।श इसका मतलब साफ थाकृ नरेंद्र मोदी को 142 करोड़ लोगों के देश का नेतृत्व करने वाले शेर के तौर पर पेश करना।उन्होंने यह भी कहा कि हमने कभी दूसरों पर हमला नहीं किया, यह पूरी तरह से भूलकर कि सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध में कितनी बड़ी संख्या में लोगों को मारा था। उन्होंने यह भी नजरअंदाज किया कि कैसे बौद्ध और जैन मंदिरों को तोड़ दिया गया और उन पर हिंदू मंदिर बनाए गए। इसके अलावा, जाति के नाम पर जुल्म दुनिया में कहीं और अनजान है। एक सोची–समझी चाल में, श्री डोभाल ने महात्मा गांधी, भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस के नाम लिए। फिर भी, अपने पूरे भाषण में, वह सबको साथ लेकर चलने, न्याय, पिछड़े तबकों के लिए बराबरी, या पुरुष–स्त्री बराबरी के लिए उनके साझी प्रतिबद्धता के बारे में एक भी शब्द नहीं बोल पाए।हजार साल पहले हुई गलतियों का बदला लेने पर उनका बार–बार जोर देना, सीधे तौर पर मध्ययुगीन काल के भारत के मुस्लिम हमलावरों की ओर इशारा करता है। यह कोई इत्तफाक नहीं है कि अगले ही दिन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमनाथ मंदिर में ऐसा ही भाषण दिया, जिसमें दावा किया गया कि मंदिर की शान अब वापस आ गई हैकृइस ऐतिहासिक सच्चाई के बावजूद कि इसे 1951 में पूरी तरह से फिर से बनाया गया था। ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री ने मंदिर की प्रतीकात्मक जगह तो चुनी, लेकिन युवाओं को सीधे संबोधित करने और बदला लेने का विचार पैदा करने का काम बड़ी चतुराई से अजीत डोभाल को सौंप दिया गया।खास बात यह है कि श्री डोभाल यह बताने में नाकाम रहे कि बदला कैसे लिया जाए, या किसके खिलाफ लिया जाए, यह देखते हुए कि महमूद गजनी बहुत पहले मर चुका है। उन्होंने इस ऐतिहासिक सच्चाई को भी नजरअंदाज कर दिया कि गजनी के अभियानों को उस समय के कई हिंदू राजाओं के समर्थन और सहयोग से मदद मिली थीकृजिनके सहयोग के बिना जरूरी आपूर्ति की कमी के कारण उनकी सेना बच नहीं सकती थी। एक खतरनाक एजेंडा सामने लाने के साथ, आरएसएस ने अब पूरे देश में हिंदू सम्मेलन करने की योजना बनायी है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत हिंदू राष्ट्र की बात करते समय कोई लाग–लपेट नहीं करते। अजीत डोभाल के भाषण को आरएसएस और भाजपा सरकार के थिंक टैंक ने अच्छी तरह से मंजूरी दी है।रणनीति साफ है रू सोमनाथ मंदिर से जुड़ी घटनाओं के हजार साल बाद पैदा हुई पीढ़ियों से बदला लेना, सांप्रदायिक दंगे करवाना और देश को अराजकता की ओर धकेलना। अब तक, हम अच्छी तरह जानते हैं कि हिंसा के कई नतीजे होते हैं। इसका असर शारीरिक घटनाओं के होने से पहले ही शुरू हो जाता है, जो मानसिक स्वास्थ्य संकट के रूप में सामने आता है। इंसानी सेहत पर शारीरिक असर जल्द ही चोट, विकलांगता और मौत के रूप में देखा जा सकता है। आर्थिक गतिविधि और शिक्षा कार्यक्रम भी बुरी तरह प्रभावित होते हैं। इससे, बदले में, पोषण का संकट और बीमारियों में बढ़ोतरी होती है। समाज के अंदर अविश्वास संकट को और बढ़ाता है। अंदरूनी झगड़े देशों को कमजोर करते हैं और बाहरी तनाव और यहां तक कि युद्धों में भी बदल सकते हैं। युद्ध सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए सबसे बड़ा खतरा बना हुआ है। इसका अवसंरचना और पर्यावरण पर बहुत बुरा असर पड़ता है और यह कई बड़ी बीमारियों को मिलाकर होने वाली मौतों और विकलांगता से भी ज़्यादा लोगों को मारता है। युद्ध तो परिवारों, समुदायों और कभी–कभी पूरी संस्कृतियों को खत्म कर देता है, जबकि पहले से उपलब्ध कम संसाधनों को स्वास्थ्य की देखभाल और जरूरी सामाजिक जरूरतों से दूर कर देता है।इसलिए यह जरूरी है कि सांप्रदायिक हिंसा और बाहरी झगड़ों से हर कीमत पर बचा जाए। यह सिर्फ लगातार सार्वजनिक शिक्षा और शांति, अहिंसा, सामाजिक मेलजोल, पुरुष–स्त्री समानता और न्याय पर आधारित मजबूत कथानकों के निर्माण से ही हासिल किया जा सकता है। सत्ता में बैठे लोगों को समाज को आगे बढ़ाना चाहिए और बदला और हिंसा का उपदेश देकर नहीं,बल्कि सबको साथ लेकर चलने वाले विकास के जरिए देश को महान बनाना चाहिए। आज दुनिया 1000 साल पहले की तुलना में कहीं ज़्यादा एक–दूसरे पर निर्भर है। अंदरूनी उथल–पुथल का अन्तरराष्ट्रीय संबंधों और आर्थिक विकास पर बुरा असर पड़ सकता है। ऐसी स्थितियों में बाहरी ताकतों के सक्रिय होने की संभावना हमेशा ज़्यादा रहती है। एक धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक समाजवादी गणराज्य के तौर पर भारत के विचार को हमें एकजुट होकर लगातार कोशिशों से बचाना और बढ़ावा देना होगा।

मतदाता सूची में वोटरों का पता गलत होना सामान्य बात.. . आयोग ने दिए सुधार के निर्देश, सपा ने उठाए थे सवाल

लखनऊ, (संवाददाता)। यूपी के राज्य निर्वाचन आयोग ने समाजवादी पार्टी की ओर से उठाए गए सवालों का जवाब देते हुए कहा कि मतदाता सूची में वोटरों का पता गलत होना एक सामान्य बात है और यह विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के कारण बिल्कुल नहीं है। आयोग ने बीएलओ को मतदाताओं के पते में सुधार का निर्देश दिया है। आयोग ने एक्स पर जवाब देते हुए कहा कि वोटर लिस्ट में विभिन्न असंबंधित व्यक्तियों के नामों के सामने मकान नंबर एक जैसा आ जाना एक बहुत आम सी गलती है जो सारी विधानसभाओं के बहुत सारे मतदान केंद्रों कि वोटरलिस्टों में विद्यमान है। यह असंतोषजनक स्थिति एसआईआर की वजह से उत्पन्न नहीं हुई है क्योंकि एसआईआर के गणना चरण में वोटर लिस्ट में वोटर के किसी भी विवरण को संशोधित नहीं किया गया है बल्कि यह स्थिति तो दशकों से चली रही है। ऐसी गलतियां कई कारणों से होती हैं जिनमें एक प्रमुख कारण यह है कि सारे गांवों में किसी भी

मकान का और शहरों में बहुत से मकानों का कोई नंबर नहीं होता इसलिए गांवों में वोटरलिस्ट में उस वोटर के नाम के सामने एक नोशनल (काल्पनिक नंबर) दिया जाता है इसलिए शहरों में बहुत से वोटरों के नाम के सामने मकान नंबर के स्थान पर 0 (जीरो) अथवा 00 (डबल जीरो) लिखा जाना एक आम चलन है। शहरों में वार्ड वार टैक्स कलेक्शन की दृष्टि से वार्ड के मकानों को एक रजिस्टर में नोशनल नंबर दिया जाता है। रामपुर जिले में मिलक नगर पालिका में ऐसा ही एक मामला सामने आया जब दो विभिन्न परिवारों का मकान नंबर विधानसभा की वोटर लिस्ट में एक जैसा पाया गया जिसे एक समाचार पत्र ने प्रमुखता से छापा। दोनों परिवार नगरपालिका के अलग–अलग वार्डों में रहते हैं परंतु परिवारों के वॉर्ड रजिस्टरों में लिखें नोशनल मकान नंबर एक जैसे हैं। विधानसभा की वोटर लिस्ट में दोनों परिवारों के वोट एक ही बूथ पर दर्ज है। उस भाग का केवल एक ही अनुभाग बना था और मकान नंबर के साथ वार्ड नंबर अंकित नहीं था इसलिए दोनों परिवारों के मकान नंबर एक समान दिख रहे हैं। वोटर लिस्ट के भागों को सही प्रकार से पर्याप्त संख्या में सही अनुभागों में ना बांटा जाना इस विसंगति का एक कारण बना। अब इस संतोषजनक स्थिति को सुधारने के लिए सभी निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को निर्देशित कर दिया गया है कि इस समस्या को जड़ से समाप्त करने के लिए सभी पोलिंग स्टेशनों के मतदान क्षेत्रों में पर्याप्त संख्या में वेल डिमार्केटेड अनुभाग बनाये जाएं जिससे न केवल बीएलओ को मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण के समय और चुनाव के समय मतदाता पर्ची बांटने के लिए वोटरों को ढूंढने में आसानी होगी बल्कि असंबंधित लोगों के मकान नंबर वोटर लिस्ट में एक समान आने की समस्या से भी कुछ हद तक निजात मिलेगी।

शीतकालीन अवकाश के बाद खुले स्कूल, कड़ाके की ठंड और कोहरे के बीच विद्यालय पहुंचे बच्चे

लखनऊ, (संवाददाता)। उत्तर प्रदेश में शीतकालीन अवकाश के बाद फिर से स्कूल खुल गए हैं। शुक्रवार सुबह घने कोहरे और कड़ाके की ठंड के बीच बच्चे स्कूल पहुंचे और प्रार्थना सभा में शामिल हुए। इस दौरान कई स्कूलों में और रास्ते पर अलाव जलाने के इंतजाम किए गए थे। बच्चों को जहां पर मौका मिला वहां अपने हाथ सेंके। वहीं, करीब सवा 10 बजे के बाद हल्की धूप खिलने से लोगों ने थोड़ी राहत महसूस की। स्कूलों में पहले की तरह शिक्षकों ने कक्षाएं लीं और कड़ाके की ठंड के बीच स्कूल आने पर उनकी प्रशंसा की। वहीं, बच्चे भी अपने साथियों से मिलकर खुश नजर आए। स्कूलों के फिर से खुलने के साथ ही दो महत्त्वपूर्ण गतिविधियां, सत्रीय परीक्षाएं और निपुण आकलन, शुरू होने वाली हैं। हालांकि, कई शिक्षक अभी भी एसआईआर प्रणाली में उलझे हुए हैं, जिससे स्कूलों के लिए एक साथ दोनों महत्वपूर्ण कार्यों को संपन्न कराना चुनौतीपूर्ण साबित हो सकता है। विद्यालयों का संचालन सुबह नौ बजे से तीन बजे तक होगा। ठंड के मौसम को ध्यान में रखते हुए, कुछ जिलों में अभी भी विद्यालय बंद रह सकते हैं। प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में 31 दिसंबर से 14 जनवरी तक शीतकालीन छुट्टियां थीं। इसके बाद 15 जनवरी को मकर संक्रांति का सार्वजनिक अवकाश था। इन छुट्टियों के बाद शुक्रवार से विद्यालय खोले जा रहे हैं। स्कूल खुलने के तुरंत बाद, 24 जनवरी से विद्यालयों में सत्रीय परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी, जो 31 जनवरी तक चलेंगी। बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा परीक्षाओं के संचालन के लिए विस्तृत निर्देश जारी किए जा चुके हैं। यह राहत दी गई है कि परीक्षाएं दिसंबर तक पढ़ाए गए पाठ्यक्रम के आधार पर ही आयोजित की जाएंगी। इसके लिए विद्यालय स्तर पर प्रश्नपत्र तैयार किए जाएंगे।

संक्षिप्त खबरें

डिप्रेशन के शिकार सराफ ने घर के आंगन में लगाया फंदा

लखनऊ, (संवाददाता)। राजधानी लखनऊ के सआदतगंज में डिप्रेशन के शिकार सराफ ने बृहस्पतिवार रात घर के आंगन में फंदा लग लिया। घरवालों के मुताबिक सराफ लगातार सोने और चांदी के भाव बढ़ने से परेशान थे। इंस्पेक्टर संतोष कुमार आर्य के मुताबिक सआदतगंज के चौपटिया में सराफ मनोज अग्रवाल रहते थे । उनकी चौक स्थित सराफ मार्केट में आभूषण की दुकान थी। घरवालों ने पूछताछ में बताया कि बाजार में सोने और चांदी के भाव बढ़ रहे थे। इस कारण मनोज को व्यापार में काफी समस्या हो रही थी। वह काफी परेशान रहने लगे थे। डिप्रेशन के चलते उन्होंने आत्महत्या कर ली। इंस्पेक्टर का कहना है की घरवालों ने किसी पर कोई आरोप नहीं लगाया है ।

शिकायतों के चलते हटाए गए राजर्षि दशरथ मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉ. सत्यजीत वर्मा

लखनऊ, (संवाददाता)। राजर्षि दशरथ मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉ. सत्यजीत वर्मा को शिकायतों के चलते हटा दिया गया है। उनके स्थान पर कन्नौज मेडिकल कॉलेज के कम्युनिटी मेडिसिन विभागाध्यक्ष डॉ. दिनेश सिंह मर्तोलिया को कार्यवाहक प्राचार्य बनाया गया है। साल भर पहले तत्कालीन प्रधानाचार्य डॉ. ज्ञानेंद्र कुमार को शिकायतों के चलते महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा के कार्यालय से संबद्ध किया गया था। उनके स्थान पर यहीं पर सर्जरी विभागाध्यक्ष रहे डॉ. सत्यजीत वर्मा को कार्यवाहक प्राचार्य बनाया गया था। पिछले करीब तीन माह से उनके खिलाफ छह विभागाध्यक्षों ने सामूहिक रूप से शिकायत की थी। वहीं, एमबीबीएस के छात्र रहे सागर पटेल की मौत के बाद परिजनों ने भी लोकायुक्त से शिकायत की थी। दोनों मामलों में जांच चल रही है। इस बीच शासन ने उन्हें हटाकर महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा के कार्यालय से संबद्ध कर दिया है।

लविवि एलटी ग्रेड भर्ती परीक्षा के चलते बदले गए सात केंद्र

लखनऊ, (संवाददाता)। लखनऊ विश्वविद्यालय ने 17 जनवरी को उप्र. लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित सहायक अध्यापक, प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी पुरुष व महिला शाखा परीक्षा के चलते विषम सेमेस्टर परीक्षा केंद्रों में बदलाव किया है। विषम सेमेस्टर की परीक्षा पहले शिया पीजी कॉलेज, नवयुग कन्या महाविद्यालय, मुमताज पीजी कॉलेज, डीएवी पीजी, शशि भूषण डिग्री, विद्यांत हिंदू पीजी और नारी शिक्षा निकेतन डिग्री कॉलेज में होनी थी लेकिन अब यहां एलटी ग्रेड भर्ती परीक्षा होनी है। इसलिए विषम सेमेस्टर परीक्षाओं के लिए लखनऊ विवि को केंद्र बनाया गया है। इस संबंध में परीक्षा नियंत्रक विद्यानंद त्रिपाठी ने निर्देश जारी किए हैं। सात कॉलेजों में 17 को होने वाली सभी परीक्षाओं के लिए अब लविवि मुख्य परिसर को परीक्षा केंद्र बनाया गया है। इसका पत्र कॉलेजों को भेज दिया गया है। विद्यार्थियों को परीक्षा केंद्र बदलाव संबंधित जानकारी हर हाल में उपलब्ध करा दी जाए। परीक्षा छूटती है तो इसकी जिम्मेदारी कॉलेज की होगी।

ताबूत की जियारत कर अजादारों ने दिया आंसुओं का पुरसा

लखनऊ, (संवाददाता)। शिया समुदाय के सातवें इमाम हजरत मूसा काजिम की शहादत पर बृहस्पतिवार को शहर के इमामबाड़ों में सैयदी मौला, सैयदी मौला की सदाएं गूंजती रहीं। हुसैनाबाद स्थित छोटा इमामबाड़ा में खादिमाने इमामे मूसा काजिम की ओर से असीर–ए–बगदाद का मातम शीर्षक से आयोजित मजलिस को मौलाना जैगम अल गरवी ने खिताब किया। मजलिस के बाद हजरत इमाम मूसा काजिम और हजरत अबु तालिब के ताबूत की जियारत कराई गई। इसके अलावा पुले बगदाद का दिलसोज मंजर पेश किया गया। मंसूर नगर स्थित इमामबाड़ा उम्मूल बनीन में मजलिस को मौलाना हैदर अब्बास रिजवी ने खिताब किया। मजलिस के बाद ताबूत की जियारत कराई गई। विक्टोरिया स्थित इमामबाड़ा नाजिम साहब में मर्सिये

की मजलिस में डॉ. अली इमाम जैदी गौहर ने मर्सिया पेश किया। शिया यूथ फेडरेशन की ओर से कर्बला मेहंदीगंज में शहीद ए काजमैन का मातम शीर्षक से मजलिस को मौलाना रहमत हुसैन नकवी ने खिताब किया। इसी तरह हजरत अबु तालिब की वफात की याद में इदारा गुलामाने अबुतालिब ने हसन पुरिया स्थित इमामबाड़ा अबुतालिब में मजलिस हुई। इसे मौलाना अबुतालिब मेहंदी ने खिताब किया। डालीगंज स्थित कर्बला नसीरुद्दीन हैदर में मौलाना सदफ जौनपुरी, मौलाना हसन जहीर,मौलाना मीसम जैदी, मौलाना सकलेन आब्दी, मौलाना बिलाल काजमी और मौलाना आबिस काजिम जरवली ने अलग–अलग मजलिसों को खिताब किया।

परीक्षा व निपुण आकलन में जुटेंगे शिक्षक, 24 से सत्रीय परीक्षाएं होंगी शुरू

लखनऊ, (संवाददाता)। उत्तर प्रदेश के परिषदीय विद्यालय शीतकालीन अवकाश के बाद 16 जनवरी से पुनः खुल रहे हैं। स्कूलों के फिर से खुलने के साथ ही दो महत्त्वपूर्ण गतिविधियां, सत्रीय परीक्षाएं और निपुण आकलन, शुरू होने वाली हैं। हालांकि, कई शिक्षक अभी भी एसआईआर प्रणाली में उलझे हुए हैं, जिससे स्कूलों के लिए एक साथ दोनों महत्वपूर्ण कार्यों को संपन्न कराना चुनौतीपूर्ण साबित हो सकता है। विद्यालयों का संचालन सुबह नौ बजे से तीन बजे तक होगा। ठंड के मौसम को ध्यान में रखते हुए, कुछ जिलों में अभी भी विद्यालय बंद रह सकते हैं। प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में 31 दिसंबर से 14 जनवरी तक शीतकालीन छुट्टियां थीं। इसके बाद 15 जनवरी को मकर संक्रांति का सार्वजनिक अवकाश था। इन छुट्टियों के बाद शुक्रवार से विद्यालय खोले जा रहे हैं। स्कूल खुलने के तुरंत बाद, 24 जनवरी से विद्यालयों में सत्रीय परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी,

जो 31 जनवरी तक चलेंगी। बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा परीक्षाओं के संचालन के लिए विस्तृत निर्देश जारी किए जा चुके हैं। यह राहत दी गई है कि परीक्षाएं दिसंबर तक पढ़ाए गए पाठ्यक्रम के आधार पर ही आयोजित की जाएंगी। इसके लिए विद्यालय स्तर पर प्रश्नपत्र तैयार किए जाएंगे। दिसंबर में शिक्षकों के एसआईआर प्रणाली से संबंधित कार्यों में व्यस्त रहने के कारण कई स्थानों पर बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हुई थी। इसी बीच, शिक्षकों के जिलों में समायोजन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है, जिसका असर शुक्रवार से स्कूल खुलने पर देखने को मिल सकता है। दूसरी ओर, 27 जनवरी से विद्यालयों का निपुण आकलन भी प्रारंभ किया जाएगा। बेसिक शिक्षा विभाग ने फरवरी तक सभी विद्यालयों में डीएलएड प्रशिक्षुओं के माध्यम से निपुण आकलन संपन्न कराने के विस्तृत निर्देश जारी कर दिए हैं। विभाग द्वारा इस कार्य के लिए आवश्यक बजट भी जारी कर दिया गया है।

संक्षिप्त खबरें

लखनऊ व्यापार मंडल का चुनाव फरवरी में : अमरनाथ मिश्र

लखनऊ, (संवाददाता)। ऐशबाग स्थित रामलीला ग्राउंड परिसर में बृहस्पतिवार को लखनऊ व्यापार मंडल की ओर से स्नेह मिलन एवं वार्षिक महोत्सव हुआ। अध्यक्ष अमरनाथ मिश्र ने बताया कि व्यापार मंडल का चुनाव फरवरी में प्रस्तावित है। इसकी तिथि की घोषणा जल्द की जाएगी। लखनऊ व्यापार मंडल व्यापारियों के सम्मान, सुरक्षा एवं अधिकारों के लिए सदैव प्रतिबद्ध रहा है। संगठन की शक्ति उसकी एकता में निहित है और आने वाले समय में मंडल व्यापारियों की समस्याओं के समाधान के लिए और अधिक प्रभावी भूमिका निभाएगा। चेयरमैन राजेंद्र कुमार अग्रवाल ने कहा कि लखनऊ व्यापार मंडल व्यापारियों का परिवार है, जो हर संघर्ष और हर परिस्थिति में अपने सदस्यों के साथ खड़ा रहता है। वरिष्ठ महामंत्री पवन मनोचा ने कहा कि आगामी चुनाव संगठन को और अधिक लोकतांत्रिक व सशक्त बनाएंगे। कोषाध्यक्ष देवेंद्र गुप्ता ने कहा कि लखनऊ व्यापार मंडल व्यापारियों के हितों की रक्षा के लिए प्रशासन से निरंतर संवाद बनाए रखेगा। कार्यक्रम में युवा अध्यक्ष मनीष गुप्ता, वरिष्ठ महामंत्री प्रियंक गुप्ता ने व्यापारियों का स्वागत किया। व्यापारियों को सम्मानित किया गया।

जय प्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय अपनाएंगे देश के शीर्ष बोर्डिंग स्कूलों का मॉडल

लखनऊ, (संवाददाता)। समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित जय प्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय अब देश के प्रतिष्ठित और सर्वश्रेष्ठ बोर्डिंग स्कूलों की सफल कार्यप्रणालियों को अपनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। इसी उद्देश्य से समाज कल्याण विभाग और बोर्डिंग स्कूल्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (बीएसएआई) के बीच आपसी सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन किया जाएगा। इस पहल के तहत गुरुवार को देहरादून स्थित द दून स्कूल में बीएसएआई से जुड़े देश के प्रतिष्ठित बोर्डिंग स्कूलों के प्राचार्यों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें सर्वोदय विद्यालयों के शैक्षणिक और आवासीय ढांचे को और अधिक सुदृढ़ बनाने पर व्यापक मंथन हुआ।बैठक में बोर्डिंग स्कूलों में अपनाई जा रही बेस्ट प्रैक्टिसेज, प्रभावी प्रशासनिक व्यवस्था, छात्र कल्याण, अनुशासन, पाठ्येतर गतिविधियों और छात्रों के सर्वांगीण विकास से जुड़े मॉडलों पर विस्तार से चर्चा की गई। समाज कल्याण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) असीम अरुण भी इस बैठक में उपस्थित रहे। उन्होंने कहा कि इस पहल का मुख्य उद्देश्य देश के सर्वश्रेष्ठ बोर्डिंग स्कूलों के सफल अनुभवों और व्यवस्थाओं को सर्वोदय विद्यालयों तक पहुंचाना है, जिससे इन विद्यालयों में शिक्षा के साथ–साथ आवासीय व्यवस्था को भी नई मजबूती मिलेगी और विद्यार्थियों का समग्र विकास सुनिश्चित हो सकेगा।राज्यमंत्री ने कहा कि सर्वोदय विद्यालयों में बोर्डिंग सुविधाओं को और प्रभावी बनाने के लिए जल्द ही सर्वोदय विद्यालयों के प्राचार्यों और शिक्षकों की एक टीम बीएसएआई से जुड़े प्रतिष्ठित बोर्डिंग स्कूलों का शैक्षणिक भ्रमण करेगी। इस भ्रमण के दौरान शिक्षण पद्धति, छात्र देखभाल प्रणाली, हॉस्टल प्रबंधन और प्रशासनिक कार्यप्रणाली का गहन अध्ययन किया जाएगा। इसके आधार पर एक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) तैयार की जाएगी, जिसे प्रदेश के सभी 125 सर्वोदय विद्यालयों में लागू किया जाएगा।

लघु उद्योग कैसे शुरू करें...लविवि में होगी पढ़ाई

लखनऊ, (संवाददाता)। स्नातक व परास्नातक के विद्यार्थी अपना लघु उद्योग कैसे शुरू करें? किस तरह रोजगार को बढ़ावा दें? इस संबंध में

अब लखनऊ विश्वविद्यालय में पढ़ाई शुरू होगी। इसके लिए आज की जरूरत के अनुसार कोर्स तैयार किए जाएंगे। लविवि जल्द ही इस दिशा में आगे की प्रक्रिया शुरू करेगा। विश्वविद्यालय प्रशासन का मानना है कि बाजार में जिन लघु उद्योगों की शुरुआत होनी चाहिए और अच्छे मुनाफे के साथ–साथ दूसरों को भी रोजगार दिया जा सकता है उनमें सब्जी मसाले, वाशिंग पाउडर, अगरबत्ती–धूपबत्ती सहित अन्य जरूरतमंद वस्तुओं के निर्माण से जुड़े उद्योग शमिल हैं। ऐसे उद्योग की शुरुआत कैसे की जा सकती है? सरकार या बैंक से कैसे मदद मिलेगी? कैसे और कहां रजिस्ट्रेशन कराना होगा? कितने बजट से शुरुआत हो सकती है? इस तरह के तमाम बिंदुओं के बारे में विद्यार्थियों को कोर्स में बताया और सिखाया जाएगा। ये कोर्स एक वर्ष की अवधि के होंगे। जल्द ही आगामी एकेडमिक काउंसिल की बैठक में इस विषय पर शिक्षकों के साथ चर्चा करके प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। विश्वविद्यालय की योजना है कि कोर्स में शामिल किसी विद्यार्थी के पास यदि कोई स्टार्टअप का आइडिया है तो वह उसे भी बता सकेगा। उस आइडिया पर मंथन कर स्टार्टअप को बढ़ावा देने के उपाय भी किए जाएंगे। इससे दूसरे विद्यार्थी भी लाभान्वित होंगे। विद्यार्थियों के मार्गदर्शन के लिए अलग–अलग उद्योगों से जुड़े विशेषज्ञों को भी आमंत्रित किया जाएगा। इनसे विद्यार्थी अपने सवालों के जवाब पा सकेंगे। कुलपति प्रो. जेपी सैनी ने बताया कि पढ़ाई के दौरान विद्यार्थियों के सुझाव भी लिए जाएंगे। मौजूदा समय में विश्वविद्यालय के कैंपस प्लेसमेंट सेल के माध्यम से विद्यार्थियों को रोजगार मिल रहा है। अब विद्यार्थी अपने छोटे–छोटे लघु उद्योग शुरू कर सकें, इसके लिए भी उन्हें तैयार करने का लक्ष्य है।

11 रेलकर्मी जीएम अवॉर्ड से अलंकृत, लखनऊ मंडल को आठ शील्ड

लखनऊ, (संवाददाता)। उत्तर रेलवे मुख्यालय की ओर से नई दिल्ली के चाणक्यपुरी में नेशनल रेल म्यूजियम में आयोजित विशिष्ट रेल सेवा महाप्रबंधक पुरस्कार (जीएम अवॉर्ड) से लखनऊ मंडल के 11 अधिकारी व कर्मचारी अलंकृत किए गए। उन्हें जीएम अवॉर्ड दिए गए। एसी एक्सप्रेस ट्रेन के रखरखाव सहित विभिन्न कार्यों के लिए लखनऊ मंडल को आठ दक्षता शील्डें भी मिलीं। लखनऊ मंडल के सीनियर डीसीएम कुलदीप तिवारी ने बताया कि उत्तर रेलवे के महाप्रबंधक अशोक कुमार वर्मा ने अधिकारियों व कर्मचारियों की सराहना की। लखनऊ मंडल के विभिन्न विभागों में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मियों को पुरस्कृत किया गया। पुरस्कार प्रतिवर्ष कर्मचारियों को व्यक्तिगत रूप से एवं विभिन्न विभागों को उनकी उत्कृष्ट एवं अनुकरणीय रेल सेवाओं के लिए महाप्रबंधक की ओर से प्रदान किया जाता है। सीनियर डीईएन भाविक बमनिया, सीनियर डीईई ओपी तिवारी, डिप्टी सीएमई आशुतोष ओझा, जूनियर इंजीनियर (पाथवे) लक्ष्मी पाल, सीनियर सेक्शन इंजीनियर आशीर्वाद सिंह कुशवाहा, असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल इंजीनियर कार्तिकेय सिंह, सीनियर सेक्शन इंजीनियर डीजल अरविंद कुमार मौर्य, चीफ वैगन मूवमेंट इंस्पेक्टर मानेंद्र प्रताप सिंह, ट्रैफिक इंस्पेक्टर राजेश कुमार, टेक्नीशियन शिवम दुबे, चीफ ऑफिस सुपरिंटेंडेंट रवेंद्र कुमार को सम्मानित किया गया। डीआरएम सुनील कुमार वर्मा ने शुभकामनाएं और बधाई दी। लखनऊ मंडल के विभिन्न विभागों को उनकी कार्यकुशलता एवं उत्कृष्ट कार्यशैली के लिए आठ दक्षता शील्ड प्राप्त हुईं। वाणिज्य विभाग को एनएफआई शील्ड, निर्माण कार्य में सर्वश्रेष्ठ इकाई शील्ड, सर्वश्रेष्ठ रनिंग रूम शील्ड विद्युत विभाग अयोध्या है।

देशप्रेम से ओतप्रोत रही उत्तरायणी कौथिग की शाम

लखनऊ, (संवाददाता)। बीरबल साहनी मार्ग स्थित गोविंद वल्लभ पंत सांस्कृतिक उपवन में चल रहे उत्तरायणी कौथिग की शाम बृहस्पतिवार को सेना दिवस के अवसर पर देशप्रेम से ओतप्रोत रही। एक ओर जहां भूतपूर्व सैनिकों को मध्य कमान के सेनाध्यक्ष रह चुके सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल योगेंद्र डिमरी ने सम्मानित किया। दूसरी तरफ गायन व नृत्य में देशप्रेम की झलक देखने को मिली। मुख्य अतिथि सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल योगेंद्र डिमरी ने दीप प्रज्ज्वलित किया। उन्होंने भूतपूर्व सैनिकों को अलंकृत कर उनकी सेवाओं को सराहा। पर्वतीय महापरिषद के अध्यक्ष गणेश जोशी ने उन्हें प्रतीक चिह्न प्रदान किया। सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास निदेशालय के अवकाशप्राप्त निदेशक अतुल कुमार व विंग कमांडर मुकेश तिवारी मौजूद रहे। इससे पहले दोपहर में एकल गायन प्रतियोगिता में विभिन्न आयुवर्गों के लोगों ने हुनर का प्रदर्शन किया। दीपा पांडेय का उत्तराखंडी निमंत्रण गीत 'सुआ रे सुआ...' व लखनऊ पब्लिक कॉलेज से केजी की छात्रा दर्शिका पाठक ने शिवरुद्राष्टक नाम गोत्रम् का मंत्रोचार किया। प्रतियोगिता के निर्णायक मंडल में गिरीश चंद्र बहुगुणा, भावना गुरुरानी व उत्तराखंड से आए लोकगायक नीरज चुफाल शामिल रहे। प्रतियोगिता के विजेताओं आनंद, विहान, आद्या, व्योम, कृतिका, देवेन और इत्यान को पुरस्कृत किया गया। नारायण पाठक व केएन चंदोला के संचालन में कवि सम्मेलन हुआ। इसमें कवियों से राष्ट्रवाद से ओतप्रोत रचनाएं सुनाकर वाहवाही लूटी। उत्तराखंड से आए लोकगायक राकेश जोशी व नीरज चुफाल के गीत दर्शकों को पसंद आए। गोमतीनगर से कलाकारों ने गोविंद्र बोरा, आनंद कपकोटी, ख्याली सिंह के नेतृत्व में वीर सैनिकों पर आधारित नृत्य प्रस्तुति की। इस अवसर पर पर्वतीय महापरिषद के गोविंद पाठक, प्रभारी महिला प्रकोष्ठ सुमन रावत, आनंद भंडारी है।

अम्बेडकर नगर के राजभर वंशीय अष्ट खम्भा स्तूप को मिलेगी नई पहचान, एक करोड़ रुपये से होगा पर्यटन विकास

लखनऊ, (संवाददाता)। राजभर समाज की शौर्यगाथा और महाराजा सुहेलदेव की गौरवशाली विरासत को नई पीढ़ी से जोड़ने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। अम्बेडकर नगर स्थित ऐतिहासिक राजभर वंशीय अष्ट खम्भा स्तूप को प्रदेश के पर्यटन मानचित्र पर विशिष्ट पहचान दिलाने के लिए राज्य सरकार एक करोड़ रुपये की धनराशि से इसका पर्यटन विकास कराएगी। यह जानकारी पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने दी।पर्यटन मंत्री ने बताया कि अम्बेडकर नगर की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत को नई पहचान देने की दिशा में यह एक अहम पहल है। जिले के लोरपुर क्षेत्र में स्थित महाराजा सुहेलदेव से जुड़ा राजभर वंशीय अष्ट खम्भा स्तूप केवल एक पुरातात्विक संरचना नहीं, बल्कि राजभर समाज के स्वाभिमान, शौर्य और सांस्कृतिक चेतना का प्रतीक है। इस स्थल के पर्यटन विकास का उद्देश्य इसकी ऐतिहासिक गरिमा को संरक्षित करते हुए इसे संस्कृति और पर्यटन के संगम के रूप में विकसित करना है, ताकि महाराजा सुहेलदेव की वीरता और राजभर समाज की परंपराएं राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक पहचान पा सकें।पर्यटन विभाग द्वारा इस परियोजना के अंतर्गत अष्ट खम्भा स्तूप परिसर का समेकित विकास किया जाएगा। इसके तहत सौंदर्यीकरण, आधुनिक प्रकाश व्यवस्था, स्वच्छ शौचालय, पेयजल, सूचना केंद्र सहित पर्यटकों की सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा। इससे न केवल स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे, बल्कि अम्बेडकर नगर को ऐतिहासिक पर्यटन के नए केंद्र के रूप में स्थापित करने में भी मदद मिलेगी।इतिहास के पन्नों में 11वीं सदी के वीर शासक महाराजा सुहेलदेव राजभर का उल्लेख उत्तर भारत की रक्षा करने वाले महान योद्धा के रूप में मिलता है। विदेशी आक्रमणों के दौर में सैय्यद सालार मसूद द्वारा किए गए हमलों से धार्मिक और सांस्कृतिक प्रतीकों को भारी क्षति पहुंची थी, जिनमें अष्ट खम्भा जैसे महत्वपूर्ण चिन्ह भी शामिल थे। इसे राजभर समाज ने अपनी आस्था और पहचान पर आघात माना। इसके बाद महाराजा सुहेलदेव ने निर्णायक युद्ध में सालार मसूद को पराजित कर क्षेत्र को पुनः सुरक्षित किया। कालांतर में अष्ट खम्भों का जीर्णोद्धार हुआ और वे सांस्कृतिक गौरव के केंद्र बने। अब पर्यटन विकास के माध्यम से यह स्थल फिर से इतिहास, संस्कृति और पर्यटन के केंद्र के रूप में उभरने जा रहा है।जयवीर सिंह ने बताया कि सरकार के सतत प्रयासों और सुदृढ़ होती कनेक्टिविटी के चलते अम्बेडकर नगर तेजी से प्रदेश के पर्यटन मानचित्र पर अपनी मजबूत पहचान बना रहा है। घाघरा नदी के तट पर बसे इस जनपद में नौकायन, तैराकी और सुंदर घाट पर्यटकों को आकर्षित कर रहे हैं। वहीं बीड़ी गांव का महादेव मंदिर, अकबरपुर–खाटेरी मार्ग स्थित शिव बाबा मंदिर, बेनीपुर के अनिरुद्ध नगर का हनुमान मंदिर तथा राज सुल्तानपुर के बाबा जी कुटी, मां कालिका मंदिर और श्री ब्रह्म बाबा मंदिर जैसे धार्मिक स्थल जनपद को आस्था और पर्यटन का महत्वपूर्ण केंद्र बना रहे हैं।पर्यटन मंत्री ने बताया कि वर्ष 2024 में अम्बेडकर नगर में 3.31 लाख पर्यटक पहुंचे थे, जबकि वर्ष 2025 में जनवरी से जून के बीच ही दो लाख से अधिक पर्यटक यहां आ चुके थे। यह आंकड़े जनपद की बढ़ती लोकप्रियता और पर्यटन संभावनाओं को स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं। अष्ट खम्भा स्तूप के पर्यटन विकास के बाद अम्बेडकर नगर को ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पर्यटन के क्षेत्र में और नई ऊंचाइयां मिलने की उम्मीद है।

जिला व्यापार बन्धु की बैठक- व्यापारी संवाद कार्यक्रम का हुआ आयोजन

(राजन तिवारी संवाददाता अयोध्या धाम)

अयोध्या।शनिवार को अपर आयुक्त रोड–1, राज्य कर अयोध्या जोन, की अध्यक्षता में जिला व्यापार बन्धु की बैठक– व्यापारी संवाद कार्यक्रमष में रूप में सम्पन्न हुई। कार्यक्रम में व्यापारिक गतिविधियाँ को प्रोत्साहन देने, पंजीयन बेस एवं राजस्व वृध्दि तथा स्थानीय स्तर पर जी0एस0टी0–2.0 में निहित व्यापारी सुविधाओं से अवगत कराने के साथ व्यापारिक गतिविधियों में आ रही समस्याओं एवं उनके निराकरण हेतु प्राप्त सुझावों को साझा करने का रहा।बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित वेद प्रकाश गुप्ता,विधायक सदर, अयोध्या ने बताया कि विद्युत आपूर्ति की समस्या व्यापारियों की सबसे बड़ी समस्या थी, जो वर्तमान में सरकार के प्रयासों से अब इतिहास बन गई है।कहा कि पूर्व की व्यवस्था, व्यापारियों का शोषण, भ्रष्टाचार आदि को समाप्त करने के लिए केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा अप्रत्यक्ष कर की व्यवस्था में क्रान्तिकारी परिवर्तन लाते हुए जी०एस०टी० एवं जी०एस०टी०–2.0 लाया गया, जो व्यापारी सवर्ग के लिए एक लाभाकारी परिवर्तन रहा है।जी०एस०टी० जागरूकता के बिन्दु पर राम आशीष पाण्डेय, उपायुक्त राज्य कर द्वारा बिन्दुवार मिलने वाले लाभों जैसे– पंजीयन, व्यापारी दुर्घटना बीमा, समाधान योजना एवं उसमें निहित सरलता से अवगत कराया गया। कार्यक्रम में राज्य कर मुख्यालय, उ0प्र0 का प्रतिनिधित्व कर रही मधुरिमा मित्रा, संयुक्त आयुक्त ने व्यापारी संवाद कार्यक्रम के माध्यम से सरकार की भवनाओं को जोड़ने का प्रयास किया और जी०एस०टी० के अन्तर्गत अपेक्षित सुधारों हेतु सुझाव, व्यापार संगठन के प्रतिनिधियों एवं उपस्थित अधिवक्ताओं से प्राप्त कराने का अनुरोध किया।अतुल सिंह, अध्यक्ष उ०प्र० ईंट निर्माता कल्याण परिषद ने जी०एस०टी० के अन्तर्गत ईंट निर्माता व्यापारियों को ष्पेशल समाधान योजनाष से बाहर रखने एवं उसके स्थान में वैट के समय लागू समाधान योजना लागू करने की माँग की। श्री अरविन्द अग्रवाल, अधिवक्ता ने अनुरोध किया कि जी०एस०टी० के अन्तर्गत पारित एकपक्षीय आदेशों की सुनवाई हेतु प्रथम अपीलीय अधिकारी की नियक्ति की जाए, जिससे छोटे–छोटे व्यापारियों के वादों का निस्तारण मा० उच्च न्यायालय में न जाकर स्थानीय स्तर पर ही किया जा सके।बैठक में संयुक्त आयुक्त राज्य कर, उपायुक्त (प्रशासन)ध संयोजक, जिला व्यापार बन्धु, राज्य कर अयोध्या, व्यापार संगठन के प्रतिनिधि विजय गुप्ता, चन्द्र प्रकाश गुप्ता, श्री के०के० गुप्ता, श्री विश्व प्रकाश रूपन व अन्य व्यापार संगठन के प्रतिनिधि उपस्थित रहें।

शिक्षा भवन पर हुआ खिचड़ी भोज का आयोजन

अयोध्या। शनिवार को शिक्षा भवन पर यूपी एजुकेशनल मिनिस्ट्रियल ऑफीसर्स एसोसिएशन उत्तर प्रदेश के पदाधिकारियों द्वारा खिचड़ी भोज कार्यक्रम का आयोजन किया गया।इस मौके पर शिक्षा विभाग के अधिकारियों के अलावा सभी कर्मचारियों ने गुनगुनी धूप में खिचड़ी का आनंद लिया।इस मौके पर खिचड़ी के महत्व के बारे में बताते हुए जिला विद्यालय निरीक्षक डॉक्टर पवन कुमार तिवारी ने कहा ऐसे आयोजन हम सभी को बीच–बीच में करते रहना चाहिए क्योंकि इससे अधिकारियों तथा कर्मचारियों के बीच की दूरियां भी कम होती है।कहा कि कोई ना कोई पर या त्योहार हम सभी को सीख देता है जिसे हमें अपने आचरण में डालना चाहिए।इस मौके पर जिला विद्यालय निरीक्षक के अलावा संयुक्त शिक्षा निदेशक माध्यमिक कौस्तुभ सिंह,एडी बेसिक,सह जिला विद्यालय निरीक्षक अवनीश पांडे,जिला समाज कल्याण अधिकारी के अलावा जिला विद्यालय निरीक्षक बुलंदशहर भी इस खिचड़ी भोज में शामिल हुए। इस मौके पर प्रदीप कुमार,पूर्व जिला मंत्री नीरज शुक्ला, पूर्व जिला अध्यक्ष विवेक सिंह,निशा मिश्रा, रविंद्र नाथ जोशी, जनार्दन यादव, शत्रुघ्न शुक्ला,शैलेंद्र वर्मा सहित कई अधिकारी कर्मचारी तथा संगठन के पदाधिकारी मौजूद रहे।

संक्षिप्त खबरें

अयोध्या में नौकाविहार अब केवल सैर नहीं,सांस्कृतिक अनुभव भी बनेगा

(डाक्टर अजय तिवारी जिला संवाददाता)

अयोध्या।अयोध्या में लगातार बढ़ रही श्रद्धालुओं और पर्यटकों की संख्या को देखते हुए उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग ने सरयू नदी में नौकाविहार को और अधिक रोचक, सुरक्षित एवं सांस्कृतिक अनुभव से समृद्ध बनाने की दिशा में अहम पहल की है। इसी क्रम में अयोध्या में सरयू नदी पर नौकायन करने वाले नाविकों के लिए तीन दिवसीय विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम (15 से 17 जनवरी) आयोजित किया गया। पर्यटन मंत्री ने स्पष्ट किया कि प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद ये नाविक अयोध्या की समृद्ध सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और पौराणिक विरासत के प्रतिनिधि के रूप में भी अपनी भूमिका निभाएंगे। नौकाविहार के दौरान श्रद्धालुओं को घाटों की प्राचीनता, सरयू नदी का धार्मिक महत्व, और अयोध्या से जुड़े ऐतिहासिक प्रसंग सुनाए जाएंगे, जिससे पर्यटकों को एक सजीव सांस्कृतिक अनुभव प्राप्त होगा।उन्होंने बताया कि प्रदेश में तेजी से विस्तार ले रहे वाटर टूरिज्म को सुरक्षित स्वरूप देने के लिए उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग लगातार ठोस कदम उठा रहा है। नाविकों के कौशल विकास और सशक्तिकरण की यह पहल सरकार की दीर्घकालिक सोच को दर्शाती है।लाइव टाइम्स से खास बातचीत में प्रशिक्षण ले रहे नाविकों ने बताया कि उन्हें श्रद्धालुओं की सुरक्षा को सर्वोपरि रखते हुए यह सिखाया गया है कि घाटों की ऐतिहासिकता और पौराणिक महत्व को रोचक कहानियों के रूप में कैसे प्रस्तुत किया जाए। नाविकों ने कहा कि अब वे पर्यटकों से संवाद, शिष्टाचार, व्यवहार और आपात स्थिति में प्रतिक्रिया जैसे विषयों पर पहले से अधिक आत्मविश्वास महसूस कर रहे हैं।नाविकों ने यह भी बताया कि प्रशिक्षण के पहले दिन अयोध्या के जिलाधिकारी निखिल टीकाराम फुंडे स्वयं कार्यक्रम में पहुंचे और उन्होंने सुरक्षा, जिम्मेदारी और पर्यटकों के साथ व्यवहार को लेकर महत्वपूर्ण जानकारियां साझा कीं। नाविकों को स्टोरीटेलिंग का प्रशिक्षण दे रहे मास्टर ट्रेनर गौरव श्रीवास्तव ने बताया कि सरयू घाट के 55 नाविकों के इस पहले समूह को प्राकृतिक आपदाओं से बचाव, डूबते श्रद्धालुओं को बचाने के उपाय, और दुर्घटना से पहले की सुरक्षा तैयारियों पर विशेष प्रशिक्षण दिया गया। उन्होंने बताया कि दूसरे दिन चिकित्सकों द्वारा प्राथमिक उपचार (फर्स्ट एड) पर व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया गया। गौरव श्रीवास्तव ने कहा, "नाविक स्थानीय हैं और अयोध्या की कहानियों को पहले से जानते हैं। हमारा प्रयास है कि वे इन कथाओं को श्रद्धालुओं के सामने प्रभावशाली और भावनात्मक रूप में प्रस्तुत कर सकें।"उन्होंने यह भी जानकारी दी कि यह प्रशिक्षण केवल शुरुआत है। आगामी चरण में अयोध्या के अन्य घाटों, विशेषकर गुप्तारघाट पर कार्यरत नाविकों को भी इसी तरह प्रशिक्षित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि यह प्रशिक्षण कार्यक्रम अयोध्या के होटल साकेत में आयोजित किया गया है, जिसका उद्देश्य नाविकों को केवल नाव चलाने तक सीमित न रखकर उन्हें डिजिटल पेमेंट, स्टोरीटेलिंग, आपदा प्रबंधन, प्राथमिक उपचार और पर्यटक व्यवहार जैसी आवश्यक दक्षताओं से लैस करना है। उन्होंने कहा कि सरयू नदी पर नौकायन को सुरक्षित और व्यवस्थित बनाना सरकार की प्राथमिकता है। पर्यटन को केवल भ्रमण नहीं, बल्कि संस्कृति और सुरक्षा से जोड़ने के उद्देश्य से मान्यवर कांशीराम पर्यटन प्रबंधन संस्थान (एमकेआईटीएम) और राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल के संयुक्त सहयोग से कुल 55 नाविकों को विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है।तीन दिवसीय इस कार्यशाला के माध्यम से अयोध्या में नौकाविहार अब केवल नदी भ्रमण नहीं, बल्कि सुरक्षा, संस्कृति और संवाद का समन्वित मॉडल बनेगा।यह पहल न केवल श्रद्धालुओं के अनुभव को समृद्ध करेगी, बल्कि स्थानीय नाविकों को आत्मनिर्भर और पेशेवर बनाने की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगी।

डीएम व एसएसपी ने सुनी तहसील दिवस मे फरियादियों की समस्या

(डाक्टर अजय तिवारी जिला संवाददाता)

अयोध्या। शनिवार को डीएम निखिल टीकाराम फुंडे ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ गौरव ग्रोवर के साथ तहसील बीकापुर के सभागार में सम्पूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया।इस मौके पर जिलाधिकारी ने समाधान दिवस के दौरान व्यक्तिगत रूप से प्रत्येक फरियादी की बात सुनी और संबंधित अधिकारियों को तत्काल आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि वे गंभीरता व संवेदनशीलता से जनता की शिकायतों को सुनें और समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करें।तहसील बीकापुर में आयोजित सम्पूर्ण समाधान दिवस के दौरान शिकायतकर्ता ग्राम डेहरियावां, विकासखण्ड बीकापुर में रास्ते की भूमि पर अवैध निर्माण हटवाने की शिकायत की,जिस पर जिलाधिकारी ने एस0एच0ओ0 बीकापुर को मामले को संज्ञान में लेकर न्यायोचित कार्यवाही करने के निर्देश दिया।शिकायत कर्ता ग्राम गौरा विकासखण्ड तारून में चकमार्ग की पटाई कराने की शिकायत में जिलाधिकारी ने खंड विकास अधिकारी व एस0एच0ओ0 तारून को मामले की जांच कर कार्यवाही करने को कहा। इसी क्रम में शिकायतकर्ता ग्राम मरूई सहाय सिंह विकासखण्ड बीकापुर में रास्ते पर जबरन मिट्टी गिराकर अवरोध करने की शिकायत में जिलाधिकारी ने एस0एच0ओ0 बीकापुर को जांच करने के निर्देश दिये।जिलाधिकारी ने बीकापुर सम्पूर्ण समाधान दिवस में आज कुल 100 शिकायतें प्राप्त हुई।जिसमें से 10 शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया। तहसील दिवस में मुख्यतः भूमि विवाद, राजस्व, सड़क, जल आपूर्ति, शिक्षा, स्वास्थ्य, राशन, पेंशन आदि से संबंधित अधिकतर शिकायतें प्राप्त हुईं, इसके निस्तारण हेतु संबंधित विभाग के अधिकारियों को गुणवत्तापूर्ण व समयबद्ध ढंग से निस्तारण के निर्देश दिए गए। सम्पूर्ण समाधान दिवस में जिला पूर्ति अधिकारी,उपजिलाधिकारी बीकापुर, क्षेत्राधिकारी बीकापुर, खण्ड विकास अधिकारी बीकापुर, खंड विकास अधिकारी तारुन, तहसीलदार बीकापुर व अन्य अधिकारी व कर्मी उपस्थित रहे।

डीएम की पहल पर खाताधारक को मिला न्याय बिना सहमति कटी धनराशि लौटाई गई जनसुनवाई में उठा मामला

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर। यूपी के जौनपुर में जिलाधिकारी डॉ. दिनेश चंद्र की सक्रियता से एक बैंक खाताधारक को बड़ी राहत मिली है। मंगलवार जनसुनवाई के दौरान लाइनबाजार थाना क्षेत्र के मुरादगंज निवासी श्रीमती माधुरी देवी पत्नी विजय कुमार ने बैंक ऑफ बड़ौदा, जेसीज चौराहा शाखा से जुड़े अपने खाते में बिना सहमति धनराशि निकाले जाने की शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में बताया गया था कि उनकी धनराशि को उनकी जानकारी व अनुमति के बिना बीमा मद में स्थानांतरित कर दिया गया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए जिलाधिकारी डॉ. दिनेश चंद्र ने तत्काल संज्ञान लेते हुए संबंधित बैंक शाखा प्रबंधक सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को आवश्यक अभिलेखों के साथ उपस्थित होने के निर्देश दिए। शुक्रवार को कलेक्ट्रेट कार्यालय में प्रकरण की सुनवाई की गई, जहां जांच के उपरांत शिकायत को सही पाते हुए शिकायतकर्ता को उसकी धनराशि उपलब्ध करा दी गई। धनराशि वापस मिलने पर श्रीमती माधुरी देवी ने जिलाधिकारी का आभार व्यक्त करते हुए शासन–प्रशासन को धन्यवाद दिया। इस अवसर पर जिलाधिकारी द्वारा उन्हें कंबल भी वितरित किया गया। जिलाधिकारी डॉ. दिनेश चंद्र ने कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार जनपद में बैंकिंग सेवाओं से संबंधित शिकायतों का त्वरित, पारदर्शी एवं निष्पक्ष निस्तारण प्रशासन की प्राथमिकता है।

जिलाधिकारी की अध्यक्षता में तहसील मड़ियाहूं में संपूर्ण समाधान दिवस आयोजित

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर (सू0वि0)। जिलाधिकारी डॉ. दिनेश चंद्र की अध्यक्षता में तहसील मड़ियाहूं के सभागार में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। समाधान दिवस के दौरान आए फरियादियों की समस्याओं को गंभीरता से सुना गया तथा संबंधित अधिकारियों को त्वरित एवं नियमानुसार कार्रवाई के निर्देश दिए गए। बसंतु मिश्रा निवासी गोपालापुर, मड़ियाहूं द्वारा उनके खेत में अवैध निर्माण के संबंध में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया, जिस पर जिलाधिकारी ने उप जिलाधिकारी मड़ियाहूं को जांच कर नियमानुसार कार्रवाई करते हुए एक सप्ताह के भीतर आख्या प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। बेअंत कुमार निवासी अहमदपुर, मड़ियाहूं द्वारा ग्रामीण सरहद पर दूसरा सरहद बनवाए जाने के संबंध में प्रार्थना पत्र दिया गया, जिस पर जिलाधिकारी ने उप जिलाधिकारी मड़ियाहूं को आवश्यक कार्रवाई

करने के निर्देश दिए। सुरजीत कुमार निवासी बीजोरा, मड़ियाहूं द्वारा पक्के रास्ते पर अवैध रूप से निर्माण किए जाने के संबंध में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया, जिस पर संबंधित अधिकारियों को नियमानुसार कार्रवाई के निर्देश दिए गए। हरि मंगल प्रजापति निवासी सुरेरी, मड़ियाहूं द्वारा प्रार्थना पत्र के माध्यम से भूमि विवाद के संबंध में अवगत कराया गया, जिस पर जिलाधिकारी ने संबंधित थाना प्रभारी को शीघ्र आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। इस दौरान वरिष्ठ अधिवक्तागण ने जिलाधिकारी को अवगत कराया कि तहसील परिसर में शौचालय की स्थिति ठीक नही होने के कारण समस्या का सामना करना पड़ता है, जिस पर जिलाधिकारी ने ई0ओ0 को सख्त निर्देश दिया कि 07 दिन की भीतर सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करायें। जिलाधिकारी के समक्ष कुल 82 शिकायते प्राप्त हुयी जिसमें से 07 का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया। तथा अवशेष प्रार्थना पत्रों को सम्बन्धित अधिकारियो को अग्रसारित करते हुए निस्तारण के निर्देश दिये गये। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने अवगत कराया कि मा0 भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जनपद की सभी विधानसभा क्षेत्रों में दिनांक 18 जनवरी 2026 को विशेष प्रगाढ पुनरीक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत सभी विद्यालय खुले रहेंगे, जहां पर बीएलओ, सुपरवाइजर, वर्तमान प्रधान, पूर्व प्रधान , कोटेदार, बीएलए एवं अन्य गणमान्य व्यक्तियों सहित आमजन की उपस्थिति में फोटोयुक्त निर्वाचक नामावली के आलेख्य प्रकाशन और ए0एस0डी0 सूची को पढ़कर सुनाया जाएगा। सभी अध्यापक बीएलओ एप के माध्यम से फॉर्म भरने में सहायता करेंगे। जनपद के सभी अधिकारी अपने–अपने बूथों पर भ्रमणशील रहेंगे। उन्होंने बताया कि ऐसे युवा जिनकी आयु 01 जनवरी 2026, 01 अप्रैल, 01 जुलाई और 01 अक्टूबर को 18 साल पूर्ण हो रही है ऐसे मतदाता नये मतदाता बनने के लिए अपना फार्म –6 भरकर जमा कर सकते है। फार्म 6 के साथ घोषणा पत्र भरना अनिवार्य है। फॉर्म–6 नए मतदाताओं का नाम जोड़ने हेतु, फॉर्म–7 मृतक अथवा नाम विलोपन की आपत्ति हेतु तथा फॉर्म–8 नाम में अशुद्धि, संशोधन अथवा बूथ परिवर्तन के लिए भरा जाएगा। इस अवसर पर उपजिलाधिकारी, तहसीलदार, क्षेत्राधिकारी, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिला विकास अधिकारी सहित अन्य जिला स्तरीय अधिकारीगण उपस्थित रहे।

अनिश्चित वैश्विक परिदृश्य में भारत की भूमिका महत्वपूर्ण : प्रो. पुरोहित

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर। यूपी के जौनपुर स्थित वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय के व्यावसायिक अर्थशास्त्र विभाग द्वारा "भारत की उभरती आर्थिक शक्ति और विकसित भारत /2047" विषय पर शनिवार को आयोजित एक दिवसीय कार्यशाला को संबोधित करते हुए दून विश्वविद्यालय, देहरादून के स्कूल ऑफ मैनेजमेंट के डीन प्रो. एच.सी. पुरोहित ने कहा कि आज वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद भारत की उभरती आर्थिक शक्ति दुनिया भर के निवेशकों के लिए एक पसंदीदा विकल्प बन रही है। उन्होंने कहा कि वैश्विक महामारी कोरोना के बाद जहां विश्व की कई बड़ी आर्थिक शक्तियां गंभीर चुनौतियों का सामना कर रही हैं, वहीं भारत अपनी दूरदर्शी आर्थिक नीतियों के कारण तेजी से उभरती आर्थिक शक्ति के रूप में स्थापित हुआ है। प्रो. पुरोहित ने कहा कि बीते वर्ष किए गए आर्थिक सुधारोंकृजैसे आयकर स्लैब में परिवर्तन एवं कर छूट के दायरे का विस्तार, जीएसटी 2.0 के अंतर्गत टैरिफ में बदलाव कर दरों में कटौती, बहुप्रतीक्षित चार श्रम संहिताओं का क्रियान्वयन तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त करने के लिए मनरेगा के दायरे का विस्तार कर गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण (जी–राम–जी) जैसे कदमकृरोजगार सृजन और ग्राम स्वराज की स्थापना की दिशा में मील का पत्थर सिद्ध होंगे। ये सभी प्रयास विकसित भारत /2047 के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायक होंगे। कार्यशाला को संबोधित करते हुए आर्थिक मामलों के विशेषज्ञ एवं चौधरी बंशी लाल विश्वविद्यालय, भिवानी (हरियाणा) के आचार्य प्रो. एस.के. सिन्हा ने कहा कि भारत की आर्थिक मजबूती का अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगाए गए अनावश्यक टैरिफ के बावजूद भारत का निर्यात निरंतर बढ़ रहा है। इससे स्पष्ट है कि भारत व्यापार और औद्योगीकरण के क्षेत्र में एक विश्वसनीय राष्ट्र के रूप में उभरा है। कार्यशाला में अतिथियों का स्वागत डॉ. आशुतोष कुमार सिंह ने किया, जबकि धन्यवाद ज्ञापन डॉ. सुशील कुमार द्वारा प्रस्तुत किया गया। मंच संचालन डॉ. राकेश कुमार उपाध्याय ने किया। इस अवसर पर डॉ. निशा पांडे, डॉ. सुशील कुमार सिंह एवं प्रिंस सिंह सहित अन्य लोग उपस्थित रहे।

संक्षिप्त खबरें

जौनपुर में सहायक अध्यापक परीक्षा शनिवार को शुरू

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर । यूपी के जौनपुर में सहायक अध्यापक (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) परीक्षा शनिवार को जनपद के विभिन्न केंद्रों पर आयोजित की जा रही है। इस परीक्षा में कुल 14,592 परीक्षार्थी शामिल होंगे। प्रशासन ने परीक्षा को सुचारु रूप से संपन्न कराने के लिए सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली हैं।नगर के टीडी कॉलेज सहित अन्य केंद्रों पर पारदर्शी परीक्षा सम्पन्न कराने को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। परीक्षा केंद्रों पर पहुंचे परीक्षार्थियों को गहन चेकिंग के बाद अंदर प्रवेश दिया गया है। सीसीटीवी कैमरे से परीक्षा की निगरानी की जा रही है। परीक्षा केंद्र पर लगातार पुलिस बल के अलावा अंतरिक मजिस्ट्रेट और स्टैटिक मजिस्ट्रेट लगातार भ्रमण कर रहे हैं। शासन स्तर से जारी गाइड लाइन का पूरी तरह से पालन कराया जा रहा है। यह परीक्षा दो पालियों में आयोजित की जाएगी। पहली पाली सुबह 9 बजे से 11 बजे तक होगी, जिसके लिए 21 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं।पहली पाली में 9,600 परीक्षार्थी शामिल होंगे। दूसरी पाली दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक चलेगी, जिसके लिए 12 केंद्र निर्धारित किए गए हैं और इसमें 4,992 परीक्षार्थी इम्तिहान देंगे। परीक्षा को नकलविहीन और निष्पक्ष ढंग से संपन्न कराने के लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं। स्टेटिक मजिस्ट्रेट, सेक्टर मजिस्ट्रेट और लगभग 800 कक्ष निरीक्षकों की तैनाती की गई है। सभी कक्ष निरीक्षकों को पहले ही प्रशिक्षण दिया जा चुका है। जिलाधिकारी डॉ. दिनेश चंद्र ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि परीक्षा के दौरान किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट चेतावनी दी कि नकल या किसी भी प्रकार की अव्यवस्था पाए जाने पर संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

जौनपुर में सुबह से छाया घना कोहरा,लोग घरों में दुबके गाड़ियों की रफ्तार हुई धीमे

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर।। यूपी के जौनपुर में एक सप्ताह बाद शनिवार को भीषण कोहरे के साथ दिन की शुरुआत हुई। हालांकि, पिछले एक सप्ताह से धूप निकलने से लोगों को कुछ राहत मिल रही थी, लेकिन ठंड का प्रकोप लगातार बना हुआ है। शनिवार को अधिकतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इस दिन आर्द्रता 84 प्रतिशत, वायु गुणवत्ता सूचकांक 206 और हवा की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटे रही। घने कोहरे और ठंडी हवाओं ने जनजीवन को प्रभावित किया है। कोहरे का सबसे अधिक असर हाईवे पर देखा जा रहा है, जहां दृश्यता 30 मीटर से भी कम हो गई है। इससे वाहन चालकों को परेशानी हो रही है और दुर्घटनाओं की आशंका बढ़ गई है। शुक्रवार को जिले का अधिकतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। उस दिन आर्द्रता 75 प्रतिशत, वायु गुणवत्ता सूचकांक 271 और हवा की गति 6 किलोमीटर प्रति घंटे मापी गई। इससे पहले गुरुवार और शुक्रवार को धूप खिलने से ठंड से थोड़ी राहत मिली थी। तेज हवाओं और कड़ाके की ठंड के कारण सड़कों पर वाहनों की आवाजाही धीमी पड़ गई है। रात में घने कोहरे के कारण बसों और ट्रेनों का परिचालन भी प्रभावित हुआ, जिससे सड़कें सुनसान रहीं। राज्य मौसम केंद्र के प्रभारी अतुल कुमार ने बताया कि तापमान में गिरावट के कारण प्रदेश के कई जिले अभी भी ठंड की चपेट में हैं। उन्होंने आगामी दिनों में आसमान में बादल छाए रहने और अधिकतम व न्यूनतम तापमान में और कमी आने की संभावना जताई है।लोग ठंड से बचने के लिय अलाव के सामने बैठ गए हैं। ट्रेनें भी धीमी रफ्तार से चल रही है कोहरे के कारण स्टेशन पर ट्रेनों को रोक कर चलाया जा रहा है। वही बच्चों के डॉ बाल रोग विशेषज्ञ डॉ विनोद सिंह ने कहा कि अचानक मौसम में परिवर्तन के कारण बच्चों को विशेष ध्यान रखें। मौसम परिवर्तन के कारण बच्चों को सांस लेने और बुखार आना, हड्डियों में अकड़न आना आदि है ।जिसके कारण माता पिता को 1से लेकर 10 वर्ष तक के बच्चों का विशेष ध्यान देना चाहिए।

यूपी का 26वां राज्य विश्वविद्यालय बना केएनपीजी कॉलेज

भदोही, (संवाददाता)। काशी नरेश राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय सूबे का 26वां राज्य विश्वविद्यालय बन गया है। बुधवार को राज्यपाल आनंदी बेन पटेल ने इसका अनुमोदन कर दिया है। विधान मंडल के दोनों सदनों से जल्द ही अन्य प्रक्रिया पूरी की जाएगी। विश्वविद्यालय बनने के बाद जिले के तीन राजकीय सहित 20 महाविद्यालय अब केएनपीजी कॉलेज से जुड़ जाएंगे। काशी नरेश राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय को लंबे समय से विश्वविद्यालय बनाने की मांग हो रही थी। एक अगस्त 1951 को स्थापित इस महाविद्यालय ने 75 साल में उच्च शिक्षा में मानकों को स्थापित किया है। बीते दिनों जिले के दौरे पर आए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 50 एकड़ जमीन की उपलब्धता होने पर महाविद्यालय को राज्य विश्वविद्यालय का दर्जा दिए जाने का वादा किया था। उन्होंने जिला प्रशासन को जमीन की तलाश करने के निर्देश दिए थे। इसके बाद डीएम शैलेश कुमार ने स्थानीय स्तर पर जमीन की तलाश कराई। राजस्व टीम की ओर से केएनपीजी की जमीन की पैमाइश कराई गई। महाविद्यालय के पास खुद की लगभग 63 एकड़ जमीन है। जमीन की उपलब्धता के बाद जिलाधिकारी ने शासन को रिपोर्ट भेजी। इसके बाद उच्च शिक्षा विभाग की टीम महाविद्यालय का निरीक्षण करने आई। 20 से 25 दिन पहले विधानसभा की अंतरिम कैबिनेट की बैठक में महाविद्यालय को राज्य विश्वविद्यालय बनाने पर मुहर लगाई गई, ।

सान्ध्य हिन्दी दैनिक देश की उपासना

स्वात्वाधिकारी में. प्रभुदयाल प्रकाशन की ओर से श्रीमती किरन देवी श्रीवास्तव मुद्रक, प्रकाशक एवं सम्पादक द्वारा देश की उपासना प्रेस, उपासना भवन, धर्मसारी, प्रेमापुर, जौनपुर उत्तर प्रदेश से मुद्रित एवं प्रकाशित।

सम्पादक
श्रीमती किरन देवी श्रीवास्तव

मो0 – 7007415808, 9415034002
Email - deshkiupasanadailynews@gmail.com

समाचार–पत्र से संबधित समस्त विवादों का न्याय क्षेत्र जौनपुर न्यायालय होगा।